लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार, 9 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 311

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते।" — अल्फ्रेड मर्सिएर

TODAY WEATHER

DAY 32° NIGHT 28°

Hi Low

यूपी के 12 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा, बनारस से सीएम योगी ने दी सौगात

यूपी सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करार किया है

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से बुधवार को प्रदेश के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगे। बड़ालालपुर स्थित ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर में सुबह 10 बजे आयोजित कार्यक्रम में ₹मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना₹ का शुभारंभ कयिा। इसका लाभ आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर शक्षिक कर सकेंगे।

आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना से प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित

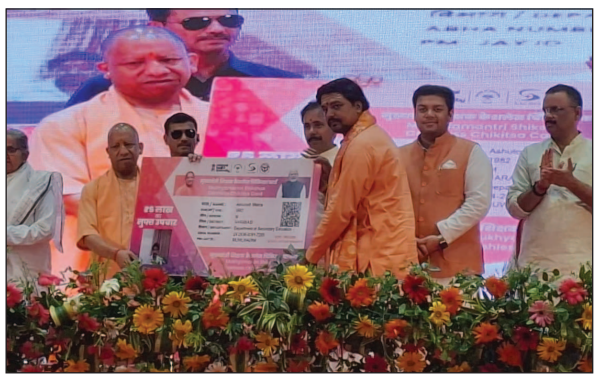

होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 15 लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित कयिा। इनमें शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया शामिल रहे।

योजना का लाभ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय, सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों, विशेष शिक्षकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों तथा अन्य पात्र शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मियों को मिलेगा।

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश के करीब 1.10 करोड़ परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 1,200 रुपये की धनराशि भी भेजा। शिक्षकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच लगभग 10 लाख शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) भी हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री ₹स्वच्छ हरित विद्यालय पुरस्कार₹ के तहत चयनित प्रदेश के 12 प्रधानाचार्यों को सम्मानित कर प्रमाण-पत्र प्रदान कयिा गया।

बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए मिलेगा पैसा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी शिक्षक या कर्मचारी के साथ अनहोनी होती है तो उनके बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, एक करोड़ रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट कवर और एक करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता कवर मिलेगा। इसके अलावा 1.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा।

1.10 करोड़ विद्यार्थियों को डीबीटी से पहुंची धनराशि

प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए योगी सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकार विद्यार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम के दौरान परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 1200 रुपये भेजे। इससे प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ होगा। बच्चे इससे अपनी आवश्यकता और आकार के अनुरूप आवश्यक सामग्री, यूनिफार्म, स्कूल बैग, जूते-मोजे, स्वेटर तथा स्टेशनरी खरीद सकेंगे।

संक्षेप

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारत आ रहे रुहत्र टैंकर पर ड्रोन से हमला, इंजन रूम में लगी आग

नई दिल्ली। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। भारत आ रहे कतर के एक एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) से लदे जहाज पर संदिग्ध ड्रोन से हमला किया गया है। एलएनजीसी अल रेकय्यात नामक यह जहाज कतर के रास लफ्फान बंदरगाह से गुजरात के दहेज बंदरगाह की ओर जा रहा था, तभी इसे निशाना बनाया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, जिससे भारी धुआं उठने लगा। हालांकि, किसी के हताहत होने या गैस रिसाव की सूचना नहीं है। जहाज पर कुल 29 चालक दल के सदस्य सवार हैं, जिनमें चार भारतीय नाविक भी शामिल हैं। सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। सूत्रों के अनुसार, 7 जुलाई को अरब सागर और ओमान की खाड़ी के मिलन बिंदु के पास ट्रांजिट के दौरान एलएनजीसी अल रेकय्यात पर संदिग्ध ड्रोन से हमला हुआ। घटना की जानकारी संबंधित समुद्री प्राधिकरणों को दे दी गई है। हमले के बावजूद जहाज अपनी यात्रा जारी रखते हुए दहेज बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटना से कुछ घंटे पहले भी फारस की खाड़ी के इसी समुद्री मार्ग से गुजर रहे दो अन्य तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया था। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी एक जहाज पर अज्ञात ड्रोन हमले की पुष्टि की है। एजेंसी के अनुसार, हमला ओमान के तट के पास हुआ, जब जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर ओमान की खाड़ी में प्रवेश कर रहा था। प्रोजेक्टाइल जहाज के बाईं ओर (पोर्ट साइड) से टकराया, लेकिन जहाज अपनी यात्रा जारी रखने में सक्षम रहा।

केरल के वायनाड में भूस्खलन से 3 मजदूरों की मौत, टनल निर्माण के दौरान मीनाक्षी पुल के पास हुआ हादसा

वायनाड। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के चलते एक बड़ा भूस्खलन (लैंडस्लाइड) हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए अब तक 6 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया है और बाकी फंसे लोगों की तलाश जारी है। यह हादसा वायनाड के मेप्पाडी स्थित कललाडी इलाके में मीनाक्षी पुल के पास हुआ है, जहां वायनाड टनल निर्माण का काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि पुल के पास स्थित पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढहकर सीधे सड़क और पास बह रही नदी में आ गिरा। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां मौजूद मजदूर टनल निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे। जानकारी के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 10 बजे घटी है। कललाडी इलाके में मीनाक्षी पुल के पास टनल की खुदाई के चलते वहां मिट्टी का एक बड़ा टीला बन गया था। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से मिट्टी का यह टीला और उसके आसपास की पहाड़ी का हिस्सा अचानक दरक गया और तेजी से नीचे की ओर आ गिरा।

'कैलाश से प्रम्बानन तक गूंज रहा महामृत्युंजय मंत्र'

इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने भव्य मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रम्बानन मंदिर दौरे के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति सुबियांतो ने 2029 से पहले जीर्णोद्धार पूरा करने का वादा लिया है। वे योजना बनाकर काम करते हैं, ऐसे में पूरा भरोसा है कि काम पूरा होगा और वे इंडोनेशिया आकर एकसाथ इसका जश्न मनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस गौरवशाली स्थल के जीर्णोद्धार का हिस्सा बनने को लेकर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा, एक हजार साल से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का एक शाश्वत प्रतीक है। संयुक्त संरक्षण परियोजना में भारतीय पक्ष से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) प्रमुख एजेंसी होगी।

योग्याकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो के साथ प्रम्बानन मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति सुबियांतो ने 2029 से पहले इस जीर्णोद्धार को पूरा करने के बाद एक बार फिर से इंडोनेशिया दौरा करने की बात कही है। उन्हें पूरा भरोसा है कि काम पूरा होगा। सरकार के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे का उद्देश्य 2018 की भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत व्यापार, सुरक्षा और दुर्लभ-पृथ्वी खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।

यहां की हवाओं में संस्कृति की सुगंध

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को जोड़ती है। इंडोनेशिया के लोग प्रम्बानन मंदिर परिसर की 'महान विरासत' को संरक्षित करने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं।संयुक्त संरक्षण परियोजना के उद्घाटन का हिस्सा बनना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, 'मैंने जो बातचीत सुनी है, उससे पता चलता है कि यहां की हवाओं में संस्कृति की सुगंध है। वह सुगंध जिसे हम भारत की धरती पर हर पल महसूस करते हैं। यह सुगंध, यह

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पहली बार गोपाल राव बोले... मुझे ट्रस्ट से नहीं हटाया गया, दान में मिला सोना-चांदी सुरक्षित

आर्यावर्त क्रांति

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें ट्रस्ट से नहीं हटाया गया है और इस संबंध में चल रही चर्चाएं तथ्यात्मक नहीं हैं।

गोपाल राव ने कहा कि जिन पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने वह नैतिक आधार पर दिया है। उन्होंने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं है कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को हटाया गया है या उनके पदों में कोई बदलाव किया गया है।

उन्होंने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए आभूषणों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि दान में

प्राप्त सोना-चांदी और अन्य कीमती आभूषण पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंदिर में प्राप्त सभी बहुमूल्य वस्तुओं का सुरक्षित रखरखाव किया जा रहा है।

गौरतलब है कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच जारी है। इस बीच गोपाल राव का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मामले को लेकर लगातार राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

पुणे में मूसलाधार बारिश का कहर : कचरे का पहाड़ गिरने से बिल्डिंग ढही, कई लोग फंसे

मुंबई, एजेंसी। पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ में बुधवार को हुई भारी बारिश के बाद, पुराने कचरे का पहाड़ जैसा ढेर पास की तीन मंज़िला इमारत पर गिर गया, जिससे वह ढह गई। इस घटना में कम से कम 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। एक अधिकारी के अनुसार, यह घटना मोशी में हुई। यहाँ इमारत का इस्तेमाल एक प्राइवेट कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था, जो नगर निकाय की ओर से उस जगह पर कचरे की प्रोसेसिंग का काम कर रही थी।

पिंपरी-चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर विजय सूर्यवंशी ने कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि भारी बारिश के कारण कचरे का ढेर ढीला हो गया और इमारत पर गिर गया। उन्होंने बताया कि प्राइवेट कंपनी के करीब 16 कर्मचारियों के इमारत के अंदर होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स , फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुँच गई हैं और बचाव अभियान चल रहा है। पिंपरी-चिंचवड़ के मेयर रवि लांडगे ने कहा कि शहर में भारी बारिश की वजह से पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इसके कारण जमा हुआ कचरा और मलबा एक ऑफिस बिल्डिंग पर गिर गया, जिससे कंक्रीट का एक स्लैब भी ढह गया। उस समय ऑफिस के सोलह कर्मचारी वहां खाना खा रहे थे; दो लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, और बाकी लोगों को बचाने का काम अभी चल रहा है। नहीं, किसी की मौत नहीं हुई है; सभी सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड, NDRF की टीम, पुलिस और स्वास्थ्य व पर्यावरण विभाग उन्हें बाहर निकालने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

पूर्व एआरटीओ के घर करोड़ों का खजाना! 13 किलो सोना, 1.62 करोड़ कैश और कई शहरों में संपत्तियों के दस्तावेज बरामद

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विजिलेंस (सतर्कता अधिष्ठान) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा के तत्कालीन एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान टीम को करीब 1.62 करोड़ रुपये नकद, 13 किलोग्राम सोना, 9 किलोग्राम चांदी, हीरे-जवाहरात और बड़ी मात्रा में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार, बरामद सोना, चांदी और आभूषणों का अनुमानित मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये बताया गया है। मामले में आगे की जांच और वैधानिक कार्रवाई जारी है। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, तलाशी के दौरान लखनऊ, नोएडा,

बाराबंकी और रायबरेली में स्थित आवासीय मकानों, प्लॉटों, फ्लैट बुकिंग और कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए। इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं।

दो कारें और रिवॉल्वर भी बरामद

छापेमारी के दौरान टीम ने टोयोटा इनोवा और हुंडई i20 कार के साथ एक रिवॉल्वर भी बरामद की। जांच में यह भी सामने आया कि मकान की साज-सज्जा और घरेलू उपकरणों पर भी लाखों रुपये खर्च किए गए थे।

2024 में दर्ज हुआ था मामला

सतर्कता अधिष्ठान के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2024 में ललित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शासन के निर्देश पर जांच जारी थी। इसी क्रम में 7 और 8 जुलाई को लखनऊ के अलीगंज स्थित आवास पर छापेमारी की गई।

टीम को मिला पुरस्कार

इस कार्रवाई की सफलता पर पुलिस महानिदेशक और निदेशक सतर्कता ने लखनऊ सेक्टर की विजिलेंस टीम को एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, शोपियां एनकाउंटर में मारा गया लश्कर का टॉप आतंकी जाकिर गनई

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। चार दिन तक चले आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद बुधवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के शीर्ष कमांडर जाकिर गनई का शव हथियार के साथ बरामद किया गया। सुरक्षा बल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को दो संदिग्ध आतंकवादी सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दिए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां के मीमंदर-चानपोरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया, जो बाद में मुठभेड़ में बदल गया।

चार दिन तक चले अभियान के बाद चानपोरा गांव से एक आतंकवादी का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान जाकिर गनई के रूप में हुई। अधिकारियों के अनुसार, वह लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय और शीर्ष कमांडर था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी इलाके में छिपे हुए थे। उनकी पहचान जाकिर गनई और लतीफ के रूप में हुई है। दोनों दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के निवासी बताए जाते हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जाकिर वर्ष 2024 से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, जबकि लतीफ ने पिछले वर्ष संगठन की सदस्यता ली थी।

यह अभियान सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने संयुक्त रूप से चलाया। अधिकारियों के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हुई। घने बाग होने के कारण अभियान कई दिनों तक जारी रहा।

फिलहाल सुरक्षा बल पूरे इलाके की सघन तलाशी ले रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई अन्य आतंकवादी छिपा न हो। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ईडी ने फ्रीज किए टीएमसी से जुड़े 3 अकाउंट, इनमें जमा हैं 440 करोड़ रुपये

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की सीएम रहीं ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने टीएमसी से जुड़े तीन अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। इन तीनों अकाउंट में 440 करोड़ रुपये जमा हैं। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत यह कार्रवाई की है। एजेंसी ने पार्टी के खातों के जरिए हुए कथित संदेहास्पद लेनदेन और चार्टर्ड विमान के खर्चों की जांच के लिए कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की।

दरअसल, ईडी ने टीएमसी के बैंक खातों से कथित हेरफेर कर 'एम्ब्रेयर' विमान और 'अगस्ता वेस्टलैंड' हेलीकॉप्टर खरीदे जाने के मामले में बीते दिन कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों का कहना है कि कोलकाता में करीब 5 ठिकानों पर रेड की गई। इनमें 'केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज' के ठिकाने भी शामिल हैं। ये 'केयरवेल एविएशन' नाम से प्राइवेट जेट किराए पर देती है। अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये 'केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' और उसकी सहयोगी यूनिट के खातों में भेजे गए। इसके बाद कंपनी ने 2023 से 2026 के बीच 82.96 करोड़ रुपये की एक और बड़ी राशि एक नई कंपनी के खाते में डाली। जांच में ये भी बात सामने आई कि इस बड़े अमाउंट में से 112 करोड़ रुपये 'एम्ब्रेयर लिगेसी 600' कॉरपोरेट विमान और 'अगस्ता वेस्टलैंड 109एसपी' हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए। इतना ही नहीं हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए विदेशों से मिले पैसे का भी इस्तेमाल किया गया था।

सड़क हादसे में बाइक सवार मां-बेटे की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

मोतिगरपुर/सुल्तानपुर। लखनऊ-बलिया हाइवे पर बुधवार दोपहर एक सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। यह घटना मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर लपटा गांव के पास हुई। पुलिस ने पिकअप और बाइक के साथ पिकअप सवार 3 लोगों को कब्जे में लेकर मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के करौंदी निवासी अमर बहादुर प्रजापति पुत्र रामतीरथ (30 वर्ष), अपनी मां ममता देवी (55 वर्ष) को मोतिगरपुर में दवा दिलाने जा रहा था। दोपहर करीब 12रू30 बजे जब वे लखनऊ-बलिया हाइवे पर स्थित शाहपुर लपटा गाँव के पास पहुंचे थे कि तभी जौनपुर से सब्जी पहुंचाकर लौट रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पहले एक पेड़ से करीब 5 फीट ऊपर उछली और फिर 30 मीटर दूर एक दीवार से टकराकर रुक गई। तेज आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो माँ-बेटे गंभीर रूप से घायल होकर हाइवे पर पड़े थे और बाइक क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। घटना के बाद अमेठी जिले के कोतवाली जगदीशपुर के घोसियाना निवासी चालक मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद खालिक और उसके सहयोगियों को राहगीरों ने दौड़कर पकड़ लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल एंबुलेंस सेवा और पुलिस को दी। सूचना के करीब 20 मिनट बाद पहुंची एंबुलेंस से मां ममता देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतिगरपुर भेजा गया। जबकि अमर बहादुर को पुलिस ने प्राइवेट वाहन से अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने अमर बहादुर को मृतक घोषित कर दिया और मां को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही ममता देवी ने भी दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अमर बहादुर चंडीगढ़ में फर्नीचर का काम करता था और तीन दिन पहले ही घर आया था। वह अपने दो भाइयों विजय और अजय में सबसे बड़ा था। उसके पिता रामतीरथ, मां गांव में रहते थे। अमर बहादुर की पत्नी अर्चना और डेढ़ साल का एक बेटा अयांश है। मोतिगरपुर थानाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

शारदा नहर में मिला अज्ञात युवक का शव, पहचान में जुटी पुलिस

कूरेभार/सुलतानपुर। कूरेभार थाना क्षेत्र के लोकेपुर-सेईया गांव के पास शारदा नहर से मंगलवार देर शाम एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है। उसने आसमानी रंग की टी-शर्ट और काले रंग का लोअर पहन रखा था। उसके दाहिने हाथ में कड़ा था। रंग सांवला, चेहरा गोल और कद लगभग पांच फीट छह इंच बताया गया है। थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे नहर में शव उतराने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। नहर में पानी अधिक होने के कारण शव को बाहर निकालने में करीब दो घंटे का समय लगा और रात लगभग नौ बजे उसे कब्जे में लिया जा सका।

कौशाम्बी में बड़ा हादसा, पंक्चर बनाते समय अज्ञात वाहन ने कुचला, पिकअप चालक समेत चार की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

कौशांबी। सैनी कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर में सड़क के किनारे पंक्चर बनाते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। हादसे में मरणासन्न लोगों को आननफानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।

सैनी कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकपुर स्थित कंगन होटल के सामने पिकअप वाहन का पंचर बदलते समय अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक समेत चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 एंबुलेंस से घायलों को सीएससी सिराथू पहुंचाया। सीएससी सिराथू से डॉक्टरों ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही चिकित्सकों ने सभी चारों युवकों को मृत घोषित कर दिया। साबिर, अकबर पुत्र शरीफ) निवासी वार्ड नंबर 10, सिराथू सैनी, अनवर पुत्र मुमताज निवासी मूरतगंज और एहसान पुत्र सपातुल्लाह निवासी रसूलपुर थाना कोखराज के रूप में की गई है। घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। कुचलने वाले वाहन की तलाश में पुलिस जुट गई है।

19 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 450 किलोग्राम लहन नष्ट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी सुल्तानपुर के नेतृत्व में बुधवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 रण विजय सिंह एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 अरुण यादव ने अपनी टीम के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम हथियानाला तथा थाना गोसाईगंज क्षेत्र के ग्राम कमलगढ़ में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 02 आबकारी अभियोग पंजीकृत किए गए तथा लगभग 19 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। इसके साथ ही लगभग 450 किलोग्राम लहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत क्षेत्र की संचालित आबकारी दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। दुकानों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तथा नियमों के अनुपालन की जांच के लिए गुप्त रूप से टेस्ट परचेज भी कराया गया। इसके अतिरिक्त कबाड़ियों की दुकानों एवं ईंट-भट्ठों की भी गहनता से जांच की गई। जनजागरूकता अभियान के तहत थाना गोसाईगंज क्षेत्र के ग्राम अगनाकोल एवं बासौडी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधियों के सहयोग से ग्राम स्तरीय चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में ग्रामीणों को अवैध शराब के सेवन एवं निर्माण से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक एवं कानूनी दुष्परिणामों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

सुबह मनाने आया, शाम को खून कर दिया... आगरा में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा, ससुराल जाने से किया था इनकार

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कोल्हाई मोहल्ले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मायके में रह रही 40 साल की कुंती देवी की उसके पति रणवीर उर्फ रानू ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पत्नी के ससुराल लौटने से इनकार करने पर आरोपी गुस्से में आ गया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस के अनुसार, कुंती देवी की शादी करीब 21 साल पहले आगरा के डौकी निवासी रणवीर उर्फ रानू से हुई थी। दंपति के दो बच्चे हैं। आरोप है कि रणवीर शराब पीने का आदी था और अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था। घरेलू विवाद बढ़ने के बाद कुंती करीब एक साल पहले अपने दोनों बच्चों के साथ मायके आकर रहने लगी थी। पति-पत्नी के बीच विवाद का मामला फिलहाल अदालत में भी विचाराधीन है।

सुबह मनाने आया, शाम को कर दी हत्या

परिजनों ने बताया कि मंगलवार सुबह रणवीर अपने पिता के साथ कुंती को वापस घर ले जाने के लिए आया था। समझौते के लिए दोनों परिवारों में पंचायती हुई। काफी समझाने के बावजूद कुंती ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों वापस लौट गए। शाम करीब चार बजे रणवीर दोबारा मायके पहुंचा। आरोप है कि इस बार वह शराब के नशे में था। घर में घुसते ही उसने कुंती के बाल पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश की। जब कुंती ने विरोध किया तो आरोपी ने जेब से चाकू निकाल लिया और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

सीने, पेट और हाथ पर किए कई वार

प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, आरोपी ने कुंती के सीने, पेट और हाथों पर लगातार कई वार किए। हमले में गंभीर रूप से घायल कुंती खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया, जबकि घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

इलाज के दौरान तोड़ा दम

डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कुंती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही जांच

एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतका के परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि इलाके के लोग भी इस वारदात से स्तब्ध हैं।

श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाली सद्बुद्धि पदयात्रा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर धाम में चढ़ावा चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बुधवार को सद्बुद्धि पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने पदयात्रा का नेतृत्व शहर अध्यक्ष की मौजूदगी में किया। पदयात्रा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से प्रारंभ होकर लाल डिग्गी चौराहा, सुपर मार्केट, डाकखाना चौराहा, कलेक्ट्रेट, तिकोनिया पार्क, दीवानी चौराहा सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पौराणिक एवं धार्मिक स्थल सीताकुण्ड धाम पहुंची। पदयात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने चढ़ावा चोरों को गिरफ्तार करो, आस्था से खिलवाड़ बंद करो, उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराओ, राम के नाम पर भ्रष्टाचार बंद करो और चोरों को बचाना बंद करो जैसे नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। पूरे मार्ग पर कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। सीताकुण्ड धाम पहुंचकर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने सरकार के जिम्मेदार लोगों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की तथा श्रीराम मंदिर धाम में चढ़ावा चोरी प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि श्रीराम के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार अब श्रीराम मंदिर के चढ़ावे पर उठे गंभीर सवालों से भाग रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस प्रकरण पर पर्दा डालने की हर कोशिश जनता देख रही है।

मथुरा में हादसा, तेज बारिश में ढही जर्जर दीवार, दंपत्ति समेत आठ साल की बेटी मलबे में दबी

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। मानसून की जो झड़ी मंगलवार से शुरू हुई वह रातभर जारी रही। कभी धीमी तो कभी तेज बारिश के चलते पुराने मकानों के लिए खतरा पैदा हो गया है। थाना मगोर्रा क्षेत्र के गांव जोगीपुरा में बुधवार सुबह लगातार हो रही तेज वर्षा के बीच एक मकान की जर्जर दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे में घर के अंदर बैठे दंपती और उनकी आठ वर्षीय बेटी मलबे के नीचे दब गए।

ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए राहत कार्य शुरू किया और तीनों को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया। सूचना पर थाना मगोर्रा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गांव जोगीपुरा निवासी प्रदीप अपनी पत्नी भगवती और आठ वर्षीय बेटी रोशनी के साथ घर में बैठे थे। इसी दौरान लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की जर्जर दीवार अचानक ढह गई। दीवार गिरते ही तीनों मलबे के नीचे दब गए।

चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

ग्रामीणों ने वर्षा के मौसम में जर्जर मकानों और दीवारों से सावधानी बरतने की अपील की है। थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि जर्जर दीवार गिरने से एक ही परिवार के तीन लोग घायल हुए हैं। सभी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

स्कूली बच्चों को सड़क पार करा रहे बस चालक की सड़क हादसे में मौत

लम्भुआ/सुल्तानपुर। लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र के डकाही गांव के पास वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

जानकारी के अनुसार लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के आल सेंट्स विद्यालय की बस से बच्चे को उतारकर चालक सड़क के दूसरे तरफ सड़क पार करा रहा था। इसी दौरान हनुमानगंज अपने घर जा रहे मोटरसाइकिल चालक की चपेट में आने से बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बस चालक दयाशंकर पाण्डेय पुत्र बुद्धिसागर पाण्डेय निवासी मलाक तुलापुर थाना शिवगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल सवार रमाशंकर सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी हनुमानगंज और साथ में रही जयमाला पत्नी प्रदीप उम्र 35 वर्ष भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ ले गई, जहां डॉक्टरों ने बस चालक दयाशंकर को मृत घोषित कर दिया।

राम मंदिर से चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार अनुकल्प, करुणेश और लवकुश की पुलिस रिमांड शुरू, अविनाश से हो चुकी पूछताछ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के परिसर के मंदिरों से चढ़ावा और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार आठ लोगों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अविनाश शुक्ला से पहले पूछताछ कर चुकी अयोध्या पुलिस ने बुधवार को तीन अन्य को रिमांड पर लिया है।

विवेचना अधिकारी सीओ आशुतोष तिवारी बुधवार को जिला कारागार पहुंचे और राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के आरोपी करुणेश पाण्डेय, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपितों को जेल निकाल कर अपनी अभिरक्षा में लिया। कोर्ट ने तीनों को 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत की है।

अविनाश शुक्ला को बीते दिनों 24 घंटे की रिमांड पर लेकर पुलिस ने चढ़ावा चोरी से खरीदी गई कार और नकद धनराशि बरामद की थी और रुपये का बंटवारा करने वाला स्थान देखा था। इस दौरान आरोपित के बयान में पुलिस को कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे है, जिनके आधार पर आज इन तीनों से बड़ी बरामदगी के संकेत हैं। पुलिस गुरुवार रात दस बजे तक इनसे पूछताछ करेगी।

सुरागों को सुलझाने के लिए पुलिस ने मांगा रिमांड

सूत्रों के अनुसार, आरोपित अविनाश शुक्ल से कस्टडी के दौरान हुई पूछताछ में मिले तथ्यों की कड़ियां अन्य आरोपितों से जुड़ती हैं। ऐसे में तीनों से आमने-सामने पूछताछ और उनके बयानों का मिलान विवेचना को नई दिशा दे सकता है। पूछताछ से चोरी की रकम, उसके बंटवारे और घटना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी खुलासा हो सकता है। इनके बयानों से अगर कोई नए तथ्य उजागर होते हैं, तो पुलिस मामले में और लोगों की भी गिरफ्तारी कर सकती है।

पुलिस के अनुसार तीनों की रिमांड अविनाश शुक्ल से मिली जानकारी को सत्यापित करने और मामले की अनसुलझी कड़ियों को सुलझाने के लिए आवश्यक है। मामले के विवेचक क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी की ओर से सोमवार को इसके लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। उन्होंने आरोपित अनुकल्प मिश्र, उसके बहनोई लवकुश मिश्र और करुणेश पांडेय की रिमांड मांगी थी। न्यायालय ने आरोपितों के अधिवक्ता कुलशेखर सिंह को तीनों से संपर्क कर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया।

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में सावन माह में प्रोटोकाल दर्शन पर लगी रोक, इस तरह सावन में कर सकेंगे बाबा का दर्शन पूजन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

वाराणसी। इस बार सावन मास में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में प्रोटोकाल दर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। मास के सोमवार को इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए आने की संभावना को देखते हुए भीड़ नियंत्रण के लिए जगह-जगह जिग जैग रेलिंग व बैरिकेडिंग की जाएगी।

इसके साथ ही बाबा का लाइव दर्शन न्यास की वेबसाइट, आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल से मिलेगा। सावन मास की तैयारियों व दर्शनार्थियों की सहूलियत के इंतजामों को लेकर मंडलायुक्त एस राजलिंगम व पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को श्रीकाशी विश्वनाथ धाम स्थित सभागार में बैठक हुई।

मंडलायुक्त ने 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले सावन मास में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया। सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने और धाम में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी के सुचारू संचालन, बिजली के उपकरणों की सेफ्टी आडिट कराने तथा गलियों में लटकते बिजली के तारों को ठीक कराने का निर्देश दिया।

सुचारू दर्शन व्यवस्था, पेयजल, मेडिकल, वृद्ध, अशक्त व दिव्यांगजन को ई-रिक्शा, पार्किंग, खोया- पाया केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में डीएम सत्येन्द्र कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

यहां से श्रद्धालुओं को मिलेगा प्रवेश

सावन मास में श्रद्धालुओं को गेट नंबर चार, काशी द्वार मार्ग 4बी, नंदू फारिया प्रवेश मार्ग, सिल्को, ढुंढिराज, सरस्वती फाटक, भैरव द्वार से (श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर घाट की तरफ से) प्रवेश मिलेगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर घाट की तरफ से श्रद्धालुओं का प्रवेश अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।

प्रत्येक सोमवार को होगा विशेष श्रृंगार

सावन मास में इस बार चार सोमवार पड़ रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इसके अलावा पूर्णिमा पर बाबा का झूला श्रृंगार किया जाएगा। भक्तों के लिए प्रतिदिन विशेष श्रृंगार होगा।

तीन अगस्त (प्रथम सोमवार): श्री शंकर स्वरूप श्रृंगार

10 अगस्त (द्वितीय सोमवार): गौरी-शंकर (शंकर-पार्वती) श्रृंगार

17 अगस्त (तृतीय सोमवार): अर्द्धनारीश्वर श्रृंगार

24 अगस्त (चतुर्थ सोमवार): रुद्राक्ष श्रृंगार

27 अगस्त (पूर्णिमा): झूला श्रृंगार

मिलेंगी ये सुविधाएं

गर्मी व उमस से राहत को लगाए जाएंगे बड़े कूलर

शीतल पेयजल व गुड़ की व्यवस्था

मेडिकल कैंप और ओआरएस का घोल

वृद्ध व अशक्त श्रद्धालुओं के लिए मैदागिन व गोदौलिया से गोल्फ कार्ट

सूक्ष्म जलपान, बिस्किट, टाफी, चाकलेट का वितरण

धाम तथा गौदोलिया से मैदागिन तक पीए सिस्टम से सूचनाओं का प्रसारण।

प्रशासन की अपील

खाली पेट कतार में न लगें

स्मार्ट वाच, पेन, मोबाइल, ईयरफोन, तंबाकू, कास्मेटिक, बड़े बैग न लाएं

दर्शन को लेकर किसी बहकावे में न आएं

दर्शन के लिए धन मांगने या दुकान से प्रसाद लेने पर दर्शन कराने की करें शिकायत।

प्रतीकात्मक कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित

आर्यावर्त संवाददाता

लंभुआ/सुल्तानपुर। ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) लंभुआ में बुधवार को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रतीकात्मक कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा वाराणसी से योजना के शुभारंभ के क्रम में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख कुंवर बहादुर सिंह, उपजिलाधिकारी प्रीति जैन, खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी लंभुआ अजय सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी भदैया शिवशंकर मिश्रा, प्रधान संघ अध्यक्ष कैलाश चंद्र दुबे, प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर सिंह तथा ब्लॉक अध्यक्ष केदार नाथ दुबे सहित अन्य अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। संचालन डॉ. राम सागर गुप्ता ने किया। ब्लॉक प्रमुख कुंवर बहादुर सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज का निर्माता होता है, इसलिए उसके सम्मान के साथ उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा भी आवश्यक है। उपजिलाधिकारी प्रीति जैन ने कहा कि यह योजना शिक्षकों के सुरक्षित चिकित्सकीय भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइयों सहित शिक्षा विभाग से जुड़े सहयोगियों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा की ऐतिहासिक पहल: ए. के. शर्मा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शिक्षकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं जनकल्याणकारी पहल है, जिससे लाखों शिक्षक और शिक्षा कर्मी लाभान्वित होंगे।ऊर्जा मंत्री बुधवार को मऊ जनपद के प्रधान समिति सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है तथा शिक्षक नई पीढ़ी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की प्राथमिकता है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक चिंताओं से काफी हद तक राहत मिलेगी और वे पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे।ए. के. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। इससे गंभीर बीमारियों के उपचार पर होने वाले आर्थिक बोझ में कमी आएगी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अंतर्गत बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (सीडब्ल्यूएसएन), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाएं, वार्डन, रसोइये तथा अन्य पात्र कार्मिक शामिल किए गए हैं। इनके आश्रित परिवार के सदस्य भी योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्वस्थ शिक्षक ही मजबूत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की नींव होते हैं। सरकार का उद्देश्य केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना नहीं, बल्कि शिक्षकों और उनके परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना प्रदेश के लाखों शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच सिद्ध होगी।कार्यक्रम के दौरान ए. के. शर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इनमें माध्यमिक शिक्षक प्रमोद सिंह, शिक्षामित्र हरी लाल यादव, बीना सिंह तथा अनुदेशक अरुण सिंह शामिल रहे।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

संक्षेप

किसान पथ पर दर्दनाक हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार की मौत

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में किसान पथ पर बुधवार को हुए एक सड़क हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए फरार वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, बुधवार को थाना पारा क्षेत्र के खुशहालगंज ओवरब्रिज ढलान के पास किसान पथ पर सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना पारा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।प्रारंभिक जांच में पता चला कि एक साइकिल सवार व्यक्ति को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस ने बिना देर किए एम्बुलेंस की सहायता से घायल को उपचार के लिए केजीएमयू मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस द्वारा मृतक की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड के आधार पर बोधी गौतम (58 वर्ष) निवासी ग्राम बड़ा गांव, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के पुत्र मिलन गौतम अस्पताल पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने घटना की जानकारी दी और आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए केजीएमयू मोर्चरी भेजा गया।पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। साथ ही दुर्घटना के कारणों और हादसे के लिए जिम्मेदार अज्ञात वाहन की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

EV सब्सिडी से यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिली रफ्तार, दोपहिया पर 5000 और बड़ी गाड़ियों पर मिल रही 20 लाख तक की छूट

लखनऊ। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और मोबिलिटी प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत दी जा रही सब्सिडी और अन्य रियायतों का असर अब पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। परिवहन विभाग के अनुसार, ईवी क्रय सब्सिडी योजना के लिए सबसे अधिक आवेदन राजधानी लखनऊ से मिले हैं। बड़े शहरों के साथ अब छोटे जिलों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ में सबसे अधिक 12,520 आवेदन मिले हैं। इसके बाद आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, सहारनपुर, गोरखपुर और प्रयागराज से आवेदन मिले हैं। छोटे जिलों में मऊ, गाजीपुर, कुशीनगर, उन्नाव, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर से भी लोगों ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। योजना के तहत दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर पांच हजार रुपये की स्टेट सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि योजना के तहत बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 20 लाख रुपये, छोटी गाड़ियों पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इससे लोगों को स्वच्छ और किफायती परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

मोहनलालगंज में बुजुर्ग ने फांसी लगाकर दी जान, आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र स्थित ग्राम केसरीखेड़ा में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है।पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह लगभग 7:30 बजे थाना मोहनलालगंज को सूचना मिली कि ग्राम केसरीखेड़ा में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ और प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान रजऊ रावत (70 वर्ष) निवासी ग्राम केसरीखेड़ा, थाना मोहनलालगंज के रूप में हुई।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रजऊ रावत ने मंगलवार रात अज्ञात कारणों से अपने घर के बरामदे में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होने पर उनके पुत्र गणेश ने उन्हें फंदे से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी गई।घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। जांच के दौरान घटनास्थल अथवा मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ।

यूपी के मंत्री बोले- दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, नहीं बचेगा

लखनऊ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में पूरे प्रकरण पर विस्तार से चर्चा हुई है और कई महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। साथ ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। अधिवक्ताओं ने आयोजित की बैठक, एफआईआर न होने पर जताई नाराजगी बार एसोसिएशन सभागार में बुधवार को श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई।

मार्निंग वॉक पर निकले चौकी प्रभारी ने दिखाई मानवता, सड़क हादसे में घायल उपनिरीक्षक की बचाई जान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह मानवता और कर्तव्यनिष्ठा का एक प्रेरणादायी उदाहरण देखने को मिला। थाना मलिहाबाद क्षेत्र की जलालपुर चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक गौरव सिंह ने अपनी नियमित मॉर्निंग वॉक के दौरान सड़क पर घायल अवस्था में पड़े एक पुलिस उपनिरीक्षक को देखकर तत्काल मदद के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने बिना समय गंवाए घायल अधिकारी को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जिससे उन्हें समय पर उपचार मिल सका। फिलहाल घायल उपनिरीक्षक का केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, जबकि हादसे के लिए जिम्मेदार अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।पुलिस के अनुसार बुधवार प्रातः चौकी प्रभारी जलालपुर उपनिरीक्षक गौरव सिंह नियमित मॉर्निंग वॉक पर थे। इसी दौरान थाना पारा क्षेत्र के तिकोनिया तिराहे के पास उन्होंने एक व्यक्ति को सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा देखा। पास जाकर जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति पुलिस विभाग में तैनात उपनिरीक्षक हैं।उपनिरीक्षक गौरव सिंह ने तत्काल मानवता का परिचय देते हुए घायल अधिकारी को अपने निजी वाहन से लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पूछताछ के दौरान घायल ने अपना नाम अनिल कुमार बताया, जो वर्तमान में थाना मानकनगर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हैं और थाना पारा क्षेत्र में रहते हैं।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उपनिरीक्षक अनिल कुमार की ड्यूटी बुधवार को थाना आशियाना क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगाई गई थी। वह सुबह अपने घर से मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान तिकोनिया तिराहे के पास पीछे से आए एक अज्ञात कार चालक ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना मानकनगर पुलिस को अवगत कराया गया। लोकबंधु अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है।पुलिस ने घायल उपनिरीक्षक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी है। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल को थाना पारा पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित थाना परिसर में खड़ा करा दिया है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के लिए जिम्मेदार अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान करने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अन्य तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। हजरतगंज कोतवाली में वर्ष 2022 में दर्ज नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 51-51 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रभावी पैरवी, समय पर गवाहों की पेशी और पुलिस-अभियोजन के समन्वित प्रयासों के चलते न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर प्रदेशभर में गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देशन में इस मुकदमे की लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रान्त वीर, अपर पुलिस उपायुक्त मध्य जितेन्द्र दूबे तथा सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज रजनीश वर्मा की निगरानी में प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह एवं उनकी टीम ने इस मामले को सजा के लिए चिन्हित कर सुनवाई की नियमित मॉनिटरिंग की।मामला वर्ष 2022 का है। हजरतगंज कोतवाली में 7 नवंबर 2022 को पीड़िता के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी दादू उर्फ आकाश ने वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान तुसी उर्फ आदित्य गुप्ता का नाम भी प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जांच पूरी होने के बाद 8 दिसंबर 2022 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र विशेष पॉक्सो न्यायालय में दाखिल किया गया।मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल पॉक्सो प्रथम न्यायालय, लखनऊ में हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष ने सुनियोजित रणनीति के साथ साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सभी गवाहों को समय से अदालत में पेश कराया गया और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी ढंग से पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध माना।न्यायालय ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसके अतिरिक्त धारा 363 में पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 365 में पांच वर्ष के कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 में एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई।

सौर ऊर्जा से बीबीएयू को 46 .48 लाख रुपये का वित्तीय लाभ, हरित परिसर निर्माण की दिशा में बड़ी उपलब्धि

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने हरित एवं सतत परिसर के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विश्वविद्यालय ने सौर ऊर्जा के प्रभावी उपयोग से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ बिजली व्यय में उल्लेखनीय कमी लाते हुए कुल 46.48 लाख रुपये का वित्तीय लाभ अर्जित किया।विश्वविद्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 29,90,583 यूनिट बिजली की खपत हुई, जबकि विश्वविद्यालय के सौर ऊर्जा संयंत्र से 9,04,953 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया गया। यह कुल विद्युत खपत का 30.26 प्रतिशत है, जो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में सौर ऊर्जा की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।सौर ऊर्जा के उपयोग से विश्वविद्यालय ने बिजली खरीद पर 42.26 लाख रुपये की प्रत्यक्ष बचत की। वहीं, नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत 49,130 यूनिट अतिरिक्त सौर ऊर्जा विद्युत ग्रिड को भेजी गई, जिसके बदले विश्वविद्यालय को 4.22 लाख रुपये का रिबेट प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रत्यक्ष बचत और रिबेट को मिलाकर विश्वविद्यालय को कुल 46.48 लाख रुपये का वित्तीय लाभ मिला।विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए 1000 किलोवाट (kWp) क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय की विद्युत आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होगा। इससे बिजली पर होने वाला खर्च और कम होगा तथा कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।इस अवसर पर कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से विश्वविद्यालय न केवल आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय भविष्य में भी हरित ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए नवाचारपूर्ण प्रयास जारी रखेगा, जिससे बीबीएयू देश के अग्रणी हरित एवं ऊर्जा-कुशल विश्वविद्यालयों में अपनी पहचान और मजबूत कर सके।

20 वर्षों से फरार वारंटी हरदोई से गिरफ्तार, गैर-जमानती वारंट पर वजीरगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ की वजीरगंज पुलिस ने करीब दो दशक से फरार चल रहे एक वारंटी को हरदोई से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की है। चोरी और चोरी का माल रखने के मामले में वांछित आरोपी लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के साथ ही उद्घोषणा और कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी थी, लेकिन वह लगातार पुलिस से बचता फिर रहा था।पुलिस के अनुसार, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट/एटीएस, लखनऊ द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में थाना वजीरगंज पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश मिले थे। यह वारंट वाद संख्या 4057/98 एवं मुकदमा अपराध संख्या 296/91 में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के तहत दर्ज मामले से संबंधित था।प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए। पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों का सत्यापन किया, स्थानीय स्तर पर सूचनाएं जुटाईं तथा तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी।इसी क्रम में बुधवार तड़के करीब पांच बजे पुलिस टीम ने जनपद हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित कवथकिया में दबिश देकर आरोपी नरेन्द्र (55 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ लंबे समय से गैर-जमानती वारंट लंबित था और वह पिछले लगभग 20 वर्षों से फरार चल रहा था।पुलिस के मुताबिक, न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण आरोपी के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत उद्घोषणा एवं संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद वह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा।पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट की जानकारी थी। उसने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था। पुलिस की नजर से बचने के लिए वह दिनभर घर से बाहर रहता था और केवल रात के समय ही चोरी-छिपे अपने घर आता था।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक सेवानन्द शर्मा तथा कांस्टेबल रोहित पासवान शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय से फरार चल रहे वारंटियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि कानून से बचने वाले आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की सीमा 25 लाख रुपये करने की मांग, आप ने दी आंदोलन की चेतावनी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। आम आदमी पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए योजना की चिकित्सा सीमा बढ़ाने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने कहा कि गंभीर बीमारियों के इलाज की मौजूदा लागत को देखते हुए योजना के तहत निर्धारित 5 लाख रुपये की सीमा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सरकार से इसे बढ़ाकर कम से कम 25 लाख रुपये करने की मांग की है।बुधवार को जारी बयान में महेंद्र सिंह ने कहा कि कैंसर, किडनी एवं लीवर प्रत्यारोपण, हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में 5 लाख रुपये की सीमा शिक्षकों और उनके परिवारों को पर्याप्त राहत नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि इलाज के बढ़ते खर्च के कारण कई शिक्षकों को अपनी जमा-पूंजी, आभूषण और यहां तक कि जमीन तक बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजना शिक्षकों की वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं करती। उनका कहना था कि जो शिक्षक अपना पूरा जीवन बच्चों के भविष्य और राष्ट्र निर्माण में समर्पित करता है, उसे गंभीर बीमारी की स्थिति में पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक अभाव के कारण किसी शिक्षक या उसके आश्रित का इलाज प्रभावित होना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है।आम आदमी पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ ने सरकार के समक्ष कई मांगें भी रखीं। पार्टी ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 25 लाख रुपये किए जाने की मांग की है। इसके अलावा कैंसर, किडनी और लीवर प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अलग विशेष चिकित्सा कोष और अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है।पार्टी ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में शिक्षकों और उनके आश्रितों को बिना अनावश्यक कागजी औपचारिकताओं के कैशलेस इलाज की सुविधा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही चिकित्सा खर्च और महंगाई को ध्यान में रखते हुए योजना की वित्तीय सीमा और बजट की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की व्यवस्था भी लागू की जाए।महेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने शिक्षकों की इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के सम्मान, स्वास्थ्य सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

क्या नितिन गडकरी की ई20 नीति की वजह से खराब हो रही हैं गाड़ियां?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर इन दिनों चौतरफा हमले हो रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ई20 पेट्रोल को वाहनों की खराबी का कारण बताया जा रहा है, तो कभी सड़कों पर उतरने की चेतावनी देकर केंद्र सरकार की एथनॉल नीति के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो लंबे समय से एथनॉल मिश्रित ईंधन को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बताते रहे हैं, अब उसी नीति को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में हैं। हम आपको बता दें कि ई20 यानी पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिश्रण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ताजा मामले में बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपनी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में आई खराबी का आरोप सीधे ई20 पेट्रोल और सरकार की नीति पर लगाया है। मनीष का दावा है कि उनकी दो महीने पुरानी और लगभग 12 हजार किलोमीटर चली गाड़ी का इंजन अचानक खराब हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्यूल टैंक से निकाले गए पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल और अशुद्धियां मिलीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह काफी भावुक नजर आए और बोले कि लाखों रुपये खर्च कर खरीदी गई गाड़ी इतनी जल्दी खराब हो जाना गंभीर चिंता का विषय है। देखा जाये तो मनीष कश्यप अकेले नहीं हैं। देशभर में हजारों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन परफॉर्मेंस कम होने और वाहनों में तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। कई वीडियो में गुलाबी रंग का पेट्रोल, टंकी में पानी जैसी परत और अन्य अशुद्धियां दिखाकर दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक है। हालांकि सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय इन दावों को खारिज कर रहे हैं। इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रूप भी ले लिया है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ई20 नीति के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। 'टीम भारत अगेंस्ट द एथनॉल स्कैम' के बैनर तले प्रस्तावित इस प्रदर्शन को एथनॉल नीति के खिलाफ पहला बड़ा सार्वजनिक आंदोलन बताया जा रहा है। पूनावाला का कहना है कि लोग एथनॉल नीति के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसकी जल्दबाजी में की गई क्रियान्वयन प्रक्रिया और उपभोक्ताओं को विकल्प न दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो कुछ लोग नितिन गडकरी के आवास के बाहर धरने पर बैठ सकते हैं। देखा जाये तो विवाद केवल वाहन खराबी तक सीमित नहीं है। एक उद्योगपति ने भी सरकार की ई20 नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि सरकार जनता के सामने इस योजना को पूरी तरह सफल बता रही है, लेकिन अदालत में इसे अभी भी 'चल रहा प्रयोग' बताया गया। हालांकि बाद में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस दावे को गलत बताया। वहीं उक्त उद्योगपति का कहना है कि असली चिंता उन उद्योगों और निवेशकों की है जिन्होंने सरकार की नीति पर भरोसा करके एथनॉल संयंत्रों में अरबों रुपये का निवेश किया। यदि एथनॉल की खरीद और मांग ही निश्चित नहीं है, तो निवेशकों को किस भरोसे निवेश के लिए प्रेरित किया गया। हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा था, जिसमें एथनॉल आवंटन प्रक्रिया को दोबारा खोलने की बात कही गई थी। इस सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठा कि सरकार द्वारा एथनॉल खरीद की बाध्यता वास्तव में कितनी मजबूत है। आलोचकों का कहना है कि यदि खरीद केवल 'सर्वश्रेष्ठ प्रयास' के आधार पर होगी तो उद्योगों की वित्तीय स्थिरता पर खतरा पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एथनॉल नीति के आर्थिक और कृषि प्रभावों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ई20 कार्यक्रम भारत को विदेशी मक्के और उससे बने उत्पादों पर अधिक निर्भर बना सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि यह नीति अब किसान केंद्रित कम और आयात आधारित ढांचे जैसी अधिक दिखाई देने लगी है। उन्होंने सरकार से ई20 की अनिवार्यता पर पुनर्विचार कर ई5 या ई10 जैसे विकल्प फिर से उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं देशी और विदेशी वाहन निर्माता कंपनियों ने ई20 पेट्रोल को लेकर मिश्रित लेकिन संतुलित रुख अपनाया है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा और किआ जैसी कंपनियों ने कहा है कि अप्रैल 2023 के बाद बने अधिकांश नए वाहन ई20 अनुकूल बनाए जा चुके हैं और उनमें इस ईंधन के इस्तेमाल से कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नहीं है। वाहन उद्योग संगठन सियाम ने भी माना है कि ई20 से माइलेज में लगभग 2 से 4 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे स्थायी इंजन क्षति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहीं महिंद्रा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि ई20 सुरक्षित तो है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ सकता है। टोयोटा सहित कई कंपनियों ने अपने नए पेट्रोल मॉडलों को ई20 अनुकूल घोषित किया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों और कंपनियों ने पुराने वाहनों में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

ब्राह्मण चला अखिलेश के संग... यूपी में चुनाव से पहले गूंजा नारा, क्या साधने में सफल होगी सपा?

मीडिया से बात करते हुए सांसद सनातन पाण्डेय ने बताया कि यह सम्मेलन 5 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाले समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित किया गया है

प्रभाकर श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश में अगले साल (2027) विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टियां अपने-अपने सामाजिक समीकरण मजबूत करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में कानपुर में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण मंच के पीछे लगा वह बैनर रहा, जिस पर लिखा था 'ब्राह्मण चला अखिलेश के संग'। इस नारे ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।

जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पाण्डेय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की।

भले ही समाजवादी पार्टी प्रदेशभर में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के नारे को प्रमुखता से आगे बढ़ा रही हो, लेकिन कानपुर में आयोजित इस सम्मेलन ने यह संकेत भी दिया गया कि बीजेपी से नाराज बताए जा रहे ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर भी पार्टी काम कर रही है। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश में ब्राह्मण समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, कथित उत्पीड़न और दर्ज मुकदमों का भी उल्लेख किया।

मीडिया से बात करते हुए सांसद सनातन पाण्डेय ने बताया कि यह सम्मेलन 5 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाले समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि अगर सूबे में दोबारा से सपा की सरकार बनती है तो पार्टी कार्यकर्ता हर जरूरतमंद के साथ खड़े होकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सम्मेलन में सांसद ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावित हुई हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।

वहीं, राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद सनातन पाण्डेय ने RSS और ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर निशाना साधते हुए उन्हें चोर करार दिया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

उत्तर प्रदेश में चुनावी मुकाबला जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे विभिन्न सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिशें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। कानपुर का यह ब्राह्मण सम्मेलन भी प्रदेश की बदलती चुनावी रणनीति का एक अहम संकेत माना जा रहा है। इससे साफ है कि पार्टी पीडीए के साथ ही अब बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण समुदाय में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कानपुर में आयोजित इस सम्मेलन ने यह संकेत भी दिया गया कि पार्टी भाजपा से नाराज बताए जा रहे ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर भी काम कर रही है।

व्यंग्य

दी ओल्ड झालमुडी डेज

इन दिनों बंगाल में एक अजीब नया संकट है। लोगों के पास कोसने के लिए पुराने मुद्दे नहीं हैं। पहले आदमी सुबह उठता था, चाय पीता था और कट मनी को कोसता था। जीवन में एक उद्देश्य था। एक स्थिरता थी। अब कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि नाश्ते के साथ किसे गाली दें। पुराने दिन याद आते हैं। क्या शानदार व्यवस्था थी।

सरकार कोलकाता से बजट भेजती थी, और वह रुपया इतना मिलनसार था कि रास्ते में सबसे मिलता जुलता चलता था। किसी को निराश नहीं करता था। वह लोकतांत्रिक रुपया था। वह पहले स्थानीय नेतृत्व का हालचाल पूछता था, फिर कार्यकर्ताओं का, फिर व्यवस्था के पुजारियों का। अंत में यदि कुछ बच जाता था तो लाभार्थी के घर भी कभी कभार दस्तक दे देता था।

नई सरकार के रुपये में वह तहजीब नहीं रही।

सीधे डी बी टी खाते में घुस जाता है। न मोहल्ले के पार्टी प्रतिनिधियों से राम राम, न नमस्कार।

पुराने दिनों में जमीनी विकास पार्टी प्रतिनिधियों के कब्जे में था। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। असली विकास वह होता है जो हर जगह मौजूद हो लेकिन कहीं पकड़ा न जाए। सड़क का पैसा सड़क में न दिखे, पुल का पैसा पुल में न दिखे, योजना का पैसा योजना में न दिखे। वह विकास का आध्यात्मिक रूप था। उसे देखने के लिए मूल रूप से तृण साधना चाहिए होती थी।

अब लोग सड़क देखकर पूछते दिख रहे हैं, यह कैसे बनी।

समय बदल गया है।

मुझे एक सज्जन मिले। बोले, व्यवस्था सुधर गई है।

मैंने कहा, दुखद समाचार है।

बोले, क्यों।

मैंने कहा, इसलिए कि पंद्रह साल का अनुभव नष्ट हो गया। हम लोगों ने एक प्रमाण पत्र बनवाने में जितना जीवन दर्शन सीखा था, उतना आजकल की पीढ़ी विश्वविद्यालय से नहीं सीख पायेगी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक भटकते हुए आदमी समझ जाता था कि संसार माया है, फाइल सत्य है और बाबू ब्रह्म है।

अब आवेदन करो और उत्तर आ जाता है।

आध्यात्मिकता का यह पतन चिंताजनक है।

पुराने समय में कट मनी केवल आर्थिक गतिविधि नहीं थी। वह लोक संस्कृति थी। वह लोक व्यवहार की तरह थी। एक आदमी पैसा देता था, दूसरा आगे बढ़ाता था, तीसरा संभालता था, चौथा वितरित करता था। पूरा तंत्र एक समूहगान की तरह काम करता था। कोई अकेला नहीं खाता था। आजकल लोग भ्रष्टाचार को भी निजी बना देना चाहते हैं। सामूहिकता का यह ह्रास दुखद है।

तब जनता भी बड़ी समझदार थी।

उसे मालूम था कि उसका काम होने वाला नहीं है, फिर भी वह आवेदन देती थी। उसे मालूम था कि शिकायत का परिणाम शिकायत ही रहेगा, फिर भी शिकायत करती थी। लोकतंत्र में विश्वास ऐसा ही होता है।

अब जनता सवाल पूछने लगी है।

पैसा कहां गया।

काम कब होगा।

लाभ किसे मिला।

यह पूछताछ की आदत बहुत खतरनाक है। यदि जनता इसी तरह पूछती रही तो कई महान परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां संग्रहालय में जाकर देखेंगी कि कभी यहां कट मनी नाम की परम्परा थी जो जनता के पैसे पर चलती थी ।

एक समय था जब हर योजना के साथ अदृश्य लाभार्थियों की लंबी सूची होती थी। अब लाभार्थी वही है , जो सच्ची मुच्ची में जिंदा है,जिसका नाम लिखा है। यह प्रशासनिक सादगी कुछ लोगों को वैसी ही लगती है जैसे रसगुल्ले से रस निकाल दिया जाए।

नई सरकार ने समाज में कुछ विचित्र परिवर्तन किए हैं। लोग अब अपने अधिकार की बात करते हैं। योजनाओं का हिसाब मांगते हैं। स्थानीय स्तर पर निगरानी करते हैं। अधिकारियों से प्रश्न पूछते हैं। पहले प्रश्न पूछना असभ्यता माना जाता था। अब उत्तर न देना असुविधाजनक माना जाने लगा है।

लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी दुर्घटना और क्या होगी।

अब तो हालत यह है कि कई लोग ईमानदारी को उपलब्धि बताने लगे हैं। जबकि हमारे यहां ईमानदारी मजबूरी मानी जाती थी।

खैर, समय की अपनी जिद होती है।

पुराने कट मनी वाले दिन अब इतिहास के एल्बम में रखी पीली पड़ चुकी तस्वीरों की तरह हैं। उन्हें देखकर कुछ लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। वे उन दिनों को याद करते हैं जब जनता विकास का कच्चा माल हुआ करती थी।

ब्लॉग

जब सुकून भी बिकने लगे

डॉ नीलम महेंद्र

सभ्यताएँ केवल अपने आविष्कारों से महान नहीं बनतीं, अपितु वे अपनी प्राथमिकताओं से इतिहास में याद रखी जाती हैं। हमारी सभ्यता ने अंतरिक्ष तक पहुँचने की क्षमता विकसित कर ली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण कर लिया, सूचनाओं को प्रकाश की गति से भी तेज़ गति से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचा दिया,लेकिन इसी सभ्यता का मनुष्य आज रात भर चैन की नींद सोने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके पास सुविधा है, साधन हैं, संसाधन हैं, पर सुकून नहीं है। और शायद हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अब सुकून भी एक उत्पाद बन चुका है।

अच्छी नींद के लिए स्लीप क्लिनिक हैं, तनाव से मुक्ति के लिए माइंडफुलनेस प्रोग्राम हैं, जंगल में समय बिताने के लिए फॉरेस्ट बाथिंग है, तारों को निहारने के लिए स्टार बाथिंग है और मोबाइल से दूर रहने के लिए डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट। इनमें से किसी उपाय पर आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इनके लाभ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। प्रश्न केवल इतना है कि जिन अनुभवों पर कभी किसी का स्वामित्व नहीं था, वे आज पैकेज और प्रीमियम सेवाओं में क्यों बदल गए? क्या हमने जीवन इतना कृत्रिम बना लिया है कि अब अपनी सबसे स्वाभाविक ज़रूरतों तक पहुँचने के लिए भी बाज़ार की मध्यस्थता आवश्यक हो गई है?

दरअसल हाल ही में तीन समाचार लगभग एक साथ चर्चा में रहे। देश के गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से बताया कि अपनी जीवनशैली में बदलाव कर उन्होंने मधुमेह पर विजय प्राप्त कर ली है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इंसुलिन एवं अन्य किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवा से भी मुक्ति पा ली है। इसी प्रकार जर्नल ऑफ एन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया कि रात में आकाश को निहारने का मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के बीच सकारात्मक संबंध है। तो अब वेलनेस थेरेपी के अंतर्गत स्टार बाथिंग (रात में खुले आकाश के नीचे लेट कर तारों को निहारना) मानसिक स्वास्थ्य की चिकित्सा का रूप ले चुका है। इसी प्रकार एक अन्य रिपोर्ट में न्यूरोलॉजिस्टों ने चेतावनी दी है कि देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखने की आदत के कारण युवाओं से लेकर छोटे बच्चों तक में माइग्रेन और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि इस प्रकार के लक्षण किसी दवा से नहीं बल्कि स्क्रीन टाइम कम करने, रात को समय पर सोने, पर्याप्त नींद लेने जैसे साधारण उपायों से ठीक हो रहे हैं।

देखने में ये तीनों समाचार अलग-अलग हैं, लेकिन इनके भीतर एक ही संदेश छिपा है,मनुष्य अपनी प्राकृतिक जीवन-लय से दूर होता जा रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में होने वाली लगभग 74 प्रतिशत मौतें गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार भारत में दस करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जबकि तेरह करोड़ से अधिक लोग प्रीडायबिटीज की स्थिति में हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भी मानती है कि अनियमित दिनचर्या, तनाव, शारीरिक निष्क्रियता और असंतुलित भोजन इस संकट के प्रमुख कारण हैं। इसे क्या कहा जाए कि एक ओर चिकित्सा विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है, तो दूसरी ओर जीवन की स्वाभाविक लय लगातार टूट रही है।

दरअसल समस्या केवल बीमारी नहीं है। समस्या यह है कि हमने सुविधा को ही विकास मान लिया है। हमने समय बचाने वाली मशीनें बनाईं, लेकिन अपने लिए समय नहीं बचा पाए। हमने श्रम कम किया, पर शरीर की सक्रियता छीन ली। हमने संचार के असंख्य साधन बना लिए, लेकिन संवाद खो दिया। हमने घरों को बड़ा बनाया, पर आँगन छोटे कर दिए। हम स्क्रीन के पहले कभी इतने जुड़े हुए नहीं थे और शायद भीतर से कभी इतने अकेले भी नहीं थे।

विकास की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन शायद उससे अधिक कुछ खो भी दिया।

आधुनिक उपभोक्तावादी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं कि वह वस्तुएँ बेचती है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह जीवन के सामान्य अनुभवों को भी असाधारण बना देती है। जिस आकाश के नीचे कभी बच्चे ध्रुव तारा पहचानते थे, आज वही स्टार बाथिंग है। जिस जंगल को भारतीय परंपरा ने तप और आत्मचिंतन का स्थान माना, वही आज वेलनेस अनुभव बन गया है। नतीजन वस्तुएँ नई नहीं हैं, उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल गया है।

आधुनिक उपभोक्तावाद की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने हमारी सबसे सामान्य आवश्यकताओं को भी विशेष अनुभव में बदल दिया। पहले स्वास्थ्य जीवन का परिणाम था, आज वह जीवन का प्रोजेक्ट बन गया है। पहले अनुशासन परिवार और परिवेश सिखाते थे, आज उसके लिए अलग से कोच, ऐप और कार्यक्रम उपलब्ध हैं। पहले सुबह की सैर किसी लक्ष्य का हिस्सा नहीं होती थी,वह दिनचर्या थी। आज वही कदम स्मार्ट वॉच गिनती है और उनकी संख्या हमारी उपलब्धि बन जाती है।

कुछ दशक पहले तक गर्मियों की रातें आँगन और छतों पर बीतती थीं। बच्चे दादी-नानी से सप्तऋषि, ध्रुव तारे और चंद्रमा की कहानियाँ सुनते हुए सो जाते थे। गाँवों में किसान खुले आकाश के नीचे रात गुज़ारते थे। तब यह कोई वेलनेस एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि जीवन की स्वाभाविक लय थी। आज वही अनुभव अंग्रेज़ी नाम, विशेषज्ञों की सलाह और पैकेजिंग के साथ लौट रहा है। यह केवल शब्दों का परिवर्तन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक स्मृति का बाज़ारीकरण है।

यही स्थिति भोजन, योग और ध्यान की भी है। सादा भोजन अब डिटॉक्स डाइट कहलाता है। उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग बन गया है। मौन माइंडफुलनेस है और योग अनेक स्थानों पर आत्मानुशासन से अधिक फिटनेस उद्योग का हिस्सा बन गया है। इन परिवर्तनों से लाभ मिल सकता है, लेकिन वे एक असुविधाजनक प्रश्न भी छोड़ जाते हैं,क्या हम अपनी परंपराओं को तब तक नहीं पहचानते जब तक वे विदेशी शब्दावली और आकर्षक पैकेजिंग में हमारे सामने वापस न आएँ?

भारतीय चिकित्सा परंपरा आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है,स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, अर्थात चिकित्सा का पहला उद्देश्य रोगी का उपचार नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा है।

आज जब चिकित्सा और अस्पताल भी एक उद्योग बन चुके हैं, हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य का पहला आधार दवा नहीं, बल्कि जीवन जीने का ढंग है। क्योंकि डॉक्टर उपचार दे सकता है, पर समय पर सोना, संतुलित भोजन करना, नियमित चलना और मानसिक संतुलन बनाए रखना अंततः व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है।

इसका अर्थ यह नहीं कि आधुनिक चिकित्सा, तकनीक या वेलनेस सेवाएँ अनावश्यक हैं। उन्होंने लाखों लोगों का जीवन बेहतर बनाया है। प्रश्न उनका अस्तित्व नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं का है। यदि समाज पहले ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करे जिनमें तनाव, निष्क्रियता और अकेलापन सामान्य हो जाएँ, और फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए उद्योग खड़े करे, तो हमें केवल उपचार पर नहीं, कारणों पर भी विचार करना होगा।

यही कारण है कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता नए वेलनेस ट्रेंड की नहीं, बल्कि जीवन की खोई हुई लय को पुनः स्थापित करने की है। स्वास्थ्य कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिसे सप्ताहांत में हासिल किया जाए, वह हर दिन जी जाने वाली छोटी-छोटी आदतों का संचय है। सुबह की धूप, थोड़ी-सी पैदल चाल, परिवार के साथ बैठकर खाया गया भोजन, पर्याप्त नींद, सीमित स्क्रीन समय और प्रकृति से नियमित संपर्क,इनका कोई विकल्प नहीं हो सकता।

सभ्यता की वास्तविक परीक्षा उसकी ऊँची इमारतों या तेज़ इंटरनेट से नहीं होगी। उसका मूल्यांकन इस बात से होगा कि उसने मनुष्य को कितना संतुलित, स्वस्थ और भीतर से शांत बनाया। यदि विकास का परिणाम यह हो कि बच्चों को खेलने के लिए कृत्रिम पार्क, बड़ों को चलने के लिए ट्रेडमिल, नींद के लिए क्लिनिक और शांति के लिए रिट्रीट खोजने पड़ें, तो हमें विकास की परिभाषा पर पुनर्विचार करना ही होगा।

शायद आने वाली पीढ़ियाँ विश्वास भी न करें कि एक समय ऐसा था जब लोग बिना किसी ऐप के अपनी नींद पूरी कर लेते थे, बिना किसी स्मार्ट वॉच के प्रतिदिन कई किलोमीटर चल लेते थे, बिना किसी स्टार बाथिंग पैकेज के तारों को निहारते थे और बिना किसी वेलनेस सदस्यता के भीतर से शांत भी रहते थे। यदि वह समय उन्हें किसी लोककथा जैसा लगे, तो समझ लीजिए कि हमने केवल जीवन की शैली नहीं बदली, जीवन का अर्थ बदल दिया है।

(लेखिका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति की सदस्य हैं)

बैंक बदलाव के पक्ष में नहीं ट्रस्ट...

SBI अफसरों से मिले गोविंद देव गिरी, अब इनके साइन बिना नहीं होगा लेन-देन

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खातों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट की पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। समिति का नेतृत्व राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन करेंगे। समिति के अन्य दो सदस्यों में पुणे के जगदीश आफले और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय शामिल हैं।

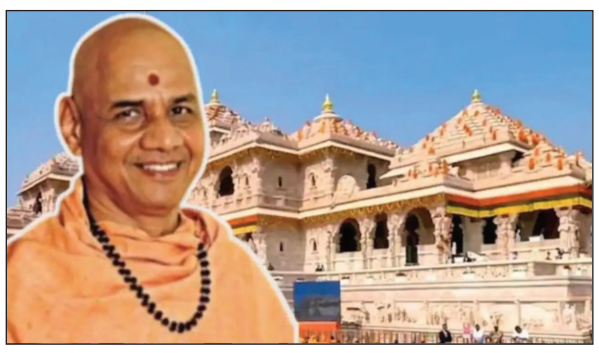

तीनों के साइन के बिना खातों से कोई लेन-देन नहीं

ट्रस्ट की ओर से दी गई जारी जानकारी के मुताबिक, इन तीनों सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना खातों से कोई लेन-देन नहीं हो सकेगा। कृष्ण मोहन को दो निजी सहयोगी रखने की भी अनुमति दी गई है, जो दैनिक कार्यों में उनकी सहायता करेंगे। यह व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से की गई है। ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक, नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है।

SBI अफसरों से मिले गोविंद देव गिरी

वहीं, उधर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बुधवार को तीर्थ क्षेत्र में एसबीआई के अधिकारियों से मिले। सूत्रों के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल, इस पूरे मामले में एसआईटी को चंपत राय ने एक पत्र लिखा था, जिसमें एसबीआई की भूमिका का जिक्र किया था।

समिति के सदस्य

कृष्ण मोहन,प्रमुख ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव
जगदीश आफले राम मंदिर निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं इंजीनियर,पुणे निवासी,
चंदन राय चार्टर्ड अकाउंटेंट

ट्रस्ट बैंक बदलाव के पक्ष में नहीं है

सूत्रों की मानें तो गोविंद देवगिरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि इस पूरे प्रक्रिया को कैसे फूलप्रूफ बनाया जाए, इसके लिए आपके पास और क्या उपाय हैं, यह हमें बताएं। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही अपना बैंक बनाना चाहता है। ट्रस्ट बैंक बदलाव के पक्ष में नहीं है।

राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद बनाई, भक्तों के चंदे से टिन्नू एंड टीम ने खरीदी जमीनें और गाड़ियां

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जैसे-जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे घोटाले को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान कई तरह की खामियां सामने आई हैं। इस बीच, राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की निशानदेही पर राम मंदिर के नाम पर बनाई गई पुरानी फर्ज़ी चंदे की रसीद बुक बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच में आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि वो न केवल चंदा चोरी करते थे बल्कि फर्ज़ी रसीद काट कर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे।

आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में टिन्नू यादव,लव कुश ,करुणेश, अनुकल्प और तमाम गिरफ्तार आरोपियों से जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता था तो ये लोग रिसीविंग के तौर पर बरामद की गई फर्ज़ी रसीद दे देते थे, ताकि किसी को कोई शक न हो और पैसा उनकी जेब में जाए।

14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर होता था पैसों बटवारा

अयोध्या पुलिस अनुकल्प, लवकुश, करुणेश से पूछताछ कर रही है। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और अविनाश शुक्ला और को चोरी के रैकेट का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। अविनाश शुक्ला के पास से गाड़ी बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पैसों बटवारा होता था।

आरोपियों से पूछताछ जारी

बताया जा रहा है कि अनुकल्प ने चोरी के पैसों से डिजायर गाड़ी खरीदी थी, उसने एक स्कॉर्पियो भी बुक की थी। वहीं आरोपी लवकुश ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर जमीन खरीदी थी, जिस पर वो तीन मंजिला इमारत बना रहा था। पुलिस इन सभी आरोपियों से इनकी प्रोपर्टी, संपत्ति, इनके बैंक खातों के बारे में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आरोपियों को इनके ठिकानों पर लेकर जाया जा सकता है।

निर्माणाधीन हनुमान घाट में रामभरोसे निर्माण का आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। पावन आदि गंगा गोमती मैया के तट पर बन रहे हनुमान घाट का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ कि उसकी गुणवत्ता पर सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों के विकास कार्य में मजबूती की जगह पीली ईंटों का सहारा लिया जा रहा है। सवाल यह है कि घाट बन रहा है या फिर पहली ही बाढ़ में बह जाने की तैयारी की जा रही है। लोगों का कहना है कि जिस घाट पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु स्नान, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करेंगे वहां यदि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ तो यह केवल सरकारी धन की बर्बादी नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ होगा। लोगों का तंज है कि कहीं ऐसा न हो कि उद्घाटन की तस्वीरें चमकें और पहली बरसात में निर्माण की हकीकत भी सामने आ जाए। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि

निर्माण में प्रयुक्त ईंट, सीमेंट और अन्य सामग्री की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि मानकों से समझौता या वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कार्यदायी संस्था पर केवल नोटिस नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए। जनता का कहना है कि धार्मिक आस्था के नाम पर यदि गुणवत्ता से समझौता किया गया तो यह आस्था के साथ-साथ जनता के भरोसे पर भी चोट होगी। जब इस संबंध में नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। उनके निर्देश पर सहायक अभियंता (एई) को तत्काल मौके पर भेजकर निर्माण कार्य और गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि जांच सिर्फ फाइलों का वजन बढ़ाती है या सचमुच जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय होती है। क्योंकि जनता पूछ रही है हनुमान घाट बनेगा मजबूत या फिर सरकारी निर्माणों की वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी जहां ईंटों से ज्यादा भरोसा जांच समितियों पर टिका रहता है।

डकैती और आय से अधिक इनकम जैसे केस, अब ईडी की रेड... जानिए सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण के बारे में

आर्यावर्त संवाददाता

झांसी। साप के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके और उनके पारिवारिक सदस्यों के लखनऊ और झांसी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने यह कार्रवाई यूपी विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट की एफआईआर के आधार पर की है। ईडी ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए।

जांच टीम सुबह-सुबह उनके ठिकानों पर पहुंच गई। बता दें कि दीप नारायण पर डकैती और आय से अधिक संपत्ति जैसे करीब 60 मामले दर्ज हैं। इस समय वह जेल में हैं और उनके पूरे साम्राज्य पर ईडी, विजिलेंस और यूपी पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है। दीप नारायण सिंह यादव यूपी के झांसी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। 2007 और 2012 में

गरौठा विधानसभा सीट से वो दो बार विधायक चुने गए।

कौन हैं सपा के पूर्व MLA दीप नारायण?

21 जुलाई 1969 को झांसी में जन्में दीप नारायण के राजनीतिक करियर की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में हुई। कांग्रेस छात्र संगठन NSUI के टिकट पर उन्होंने बुंदेलखंड इंटर कॉलेज से छात्रसंघ का चुनाव जीता। 1992 में बुंदेलखंड कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष बने। इसी दौरान मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

दीप नारायण 2007 में पहली बार बने विधायक

1991 में दीप नारायण समाजवादी युवजन सभा के झांसी जिला अध्यक्ष बने। इसके करीब दो साल बाद वो झांसी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और इस पद पर वो 1998 तक रहे। सपा में उन्होंने जिलाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, लोहिया वाहिनी के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों की कमान संभाली। 2007 में झांसी के गरौठा विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए। 2012 में दोबारा जीते। मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

दीप नारायण पर डकैती-रंगदारी जैसे दर्जनों केस

दीप नारायण पर मारपीट, धमकी, रंगदारी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। अब तक उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। पिछले साल नवंबर मोंठ के भुजौंद गांव निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने दीप नारायण और उनके साले अनिल मामा सहित अन्य लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप ये लगाया गया कि वे उनकी पुश्तैनी जमीन हड़पना चाहते थे। जब उन्होंने (प्रेम सिंह) इसके मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। जान से भी मारने की धमकी दी गई। इतना ही उनके साथ लूटपाट भी कई। साथ ही 20 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी गई। इसके बाद दीप नारायण कई दिनों तक फरार रहे और फिर उन्होंने सरेंजर कर दिया। इसके बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी मुकदमा दर्ज है।

मार्ग की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को सिकरारा क्षेत्र के सतलपुर गांव के दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सिकरारा- अजोसी मुख्य मार्ग की बदहाली को लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सिकरारा-अजोसी मुख्य मार्ग पिछले 7-8 वर्षों से अत्यधिक जर्जर है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण स्थानीय निवासियों, छात्रों, बुजुर्गों और राहगीरों को प्रतिदिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की बदहाली के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें लोग घायल हो रहे हैं।ग्रामीण महादेव यादव ने जानकारी दी कि गहरे गड्ढों के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे जानमाल के नुकसान का खतरा बना रहता है। खराब सड़क के कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है, जिससे लोगों का समय और संसाधन बर्बाद होते हैं। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम और बढ़ जाता है। रुके हुए गंदे पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका है।इसके अतिरिक्त, सड़क की दुर्दशा के कारण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहन समय पर प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।

ग्रेटर नोएडा में महिला ने ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, सोसायटी गेट पर स्कूल बस का इंतजार कर रहे 5 बच्चों को रौंदा

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित पंचशील ग्रीन-2 सोसायटी के बाहर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि कार चलाना सीख रही एक महिला ने स्कूल जाने को तैयार बच्चों को रौंद डाला। आनन-फानन में सभी बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

सोसायटी के निवासियों के अनुसार, महिला ने कार चलाते समय ब्रेक की जगह गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्कूल बस का इंतजार कर रहे बच्चों की ओर बढ़ गई। हादसे में पांच स्कूली बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।

बताया जा रहा है कि महिला भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कार लेकर निकली थी। इसी दौरान वह कथित तौर पर ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रही थी। सोसायटी के गेट से बाहर निकलते समय कार का संतुलन बिगड़ गया और महिला ने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया। तेज रफ्तार कार पहले सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी से टकराई। टक्कर के बाद भी कार नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए स्कूल बस का इंतजार कर रहे पांच बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया।

चीख सुन पहुंचे सोसायटी के लोग

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर बच्चों को कार के नीचे और आसपास से निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची और सभी बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार, सभी बच्चों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सोसायटी निवासियों का आरोप है कि हादसे के बाद महिला अपनी कार लेकर मौके से चली गई। घटना से नाराज बच्चों के अभिभावकों और सोसायटी के निवासियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुबह के समय यहां बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे बस का इंतजार करते हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

सोसायटी के लोगों का यह भी कहना है कि हादसे के दौरान महिला मोबाइल फोन पर ध्यान दे रही थी। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी तक कोई पुष्टि या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके। थाना प्रभारी बिसरख मुनेन्द्र सिंह का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सोसायटी के निवासियों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल के समय सोसायटी के बाहर ट्रैफिक नियंत्रण, स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

कादीपुर विधानसभा की राजनीति में हलचल तेज

कूरेभार/सलतानपुर। बुधवार को ब्लाक कूरेभार के रुसहा मठिया (सैदखानपुर) निवासी सुअजीत कुमार को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति, विशेषकर विधानसभा 191 कादीपुर (सुलतानपुर) में हलचल तेज हो गई है। बुधवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली में पी.पी. माधवन के सहयोगी नंदलाल पासी के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम से उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस बैठक में विधानसभा 191 कादीपुर (सुल्तानपुर) से आगामी चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर भी सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रोटोकॉल और वीआईपी दर्शन होंगे बंद, काशी के लोगों के लिए होगी अलग व्यवस्था

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस बार पूरे सावन महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की विशेष सिफारिश या वीआईपी एंट्री नहीं मिलेगी और सभी श्रद्धालुओं को सामान्य कतार में लगकर ही दर्शन करने होंगे। इसके साथ ही प्रशासन ने दलालों और फर्जी वीआईपी दर्शन के झांसे से भी सावधान रहने की अपील की है।

इस वर्ष सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 (रक्षाबंधन) तक रहेगा। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सावन को लेकर

वाराणसी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की संयुक्त बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया है कि पूरे सावन के महीने के दौरान प्रोटोकॉल और वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मंदिर प्रशासन ने साफ कहा है कि पूरे सावन महीने में वीआईपी या प्रोटोकॉल के जरिए दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति की विशेष दर्शन की सिफारिश या अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी के बहकावे या लालच में न आएं और सिर्फ सामान्य कतार में लगकर ही दर्शन करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी वीआईपी या विशेष व्यक्ति प्रोटोकॉल के लिए अनुरोध न भेजे, क्योंकि ऐसे सभी अनुरोध खारिज कर दिए जाएंगे। मंदिर प्रशासन ने लोगों को दलालों से भी सावधान रहने की सलाह दी है।

श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश के प्रमुख द्वार इस प्रकार हैं...

गेट नंबर-4
काशी द्वार मार्ग 4B
नंदू फारिया प्रवेश मार्ग
सिल्को प्रवेश मार्ग
ढुंढिराज प्रवेश मार्ग
सरस्वती फाटक प्रवेश मार्ग
भैरव द्वार प्रवेश मार्ग (श्री काशी विश्वनाथ मंदिर घाट की ओर से)

धाम में सामान्य रूप से इन सभी द्वारों से श्रद्धालुओं का प्रवेश होता है। हालांकि, गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर घाट की ओर से श्रद्धालुओं का प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

काशीवासियों को विशेष सौगात

सरकार के निर्देश पर निर्णय लिया गया है कि काशी के लोगों के लिए सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार और पर्व दिवसों को छोड़कर रोज सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और शाम 4 बजे से 5 बजे तक झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

की जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग

जो श्रद्धालु किसी कारणवश धाम नहीं पहुंच सकते, उनके लिए पूरे पवित्र सावन माह में श्री काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन-पूजन की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी रहेगी। लाइव दर्शन मंदिर न्यास की वेबसाइट, मंदिर न्यास के आधिकारिक यूट्यूब चैनल तथा आधिकारिक प्रसारण साझेदार टाटा स्काई के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।

किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?

बैठक में निर्णय लिया गया है कि धाम में प्रवेश से पहले श्रद्धालु प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएं, जैसे स्मार्ट वॉच (डिजिटल घड़ी), मोबाइल फोन, ईयरफोन, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ, कॉस्मेटिक सामान, बड़े बैग तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं अपने साथ लेकर कतार में न लगें।

श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे इन वस्तुओं को अपने होटल, घर या ठहरने के स्थान पर ही छोड़कर दर्शन के लिए आएं, अन्यथा उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से इन नियमों का पालन कर दर्शन व्यवस्था को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने में सहयोग करने की अपील की है।

जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े, लात-घूंसे चले

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह में जमीन विवाद की शिकायत करने पुलिस के पास जा रहे एक ही परिवार के दो पक्ष सड़क पर भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे चले, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। सड़क से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नही मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। दरअसल, मंगलवार को बारिश में कच्चा मकान गिर गया था। बड़ा भाई मकान का मरम्मत करवा था। लेकिन उसकी मां और छोटे भाई ने गाली-गल्लौज करते हुए मकान की मरम्मत करवाने से रोक दिया।इसके बाद बड़े भाई ने डॉयल 112 को बुलाया तो पीआरडी पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर जाने का निर्देश दिया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जरौटा ओझापुर गांव निवासी रामप्रवेश पुत्र रामप्रसाद का अपने छोटे भाई सुरेश से 2 महीने से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी मामले में शिकायत दर्ज कराने दोनों पक्ष थाने जा रहे थे। रामप्रवेश ने बताया कि मंगलवार को भारी बारिश होने के कारणरामप्रवेश पर रखा नरिया गिर गया था। आज उसी का छवाया जा रहा था। लेकिन सुरेश, मां गीता और अपने पत्नी ललिता के साथ आकर गाली गलौज करते हुए रोकने लगा। इसकी सूचना मैंने डॉयल 112 पर दी। मौके पर पहुंचे पीआरडी पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर जाने का निर्देश दिया।

पेट की दिक्कत मानकर हार्ट अटैक के लक्षणों को तो नहीं कर रहे इग्नोर? लापरवाही ले लेगी जान

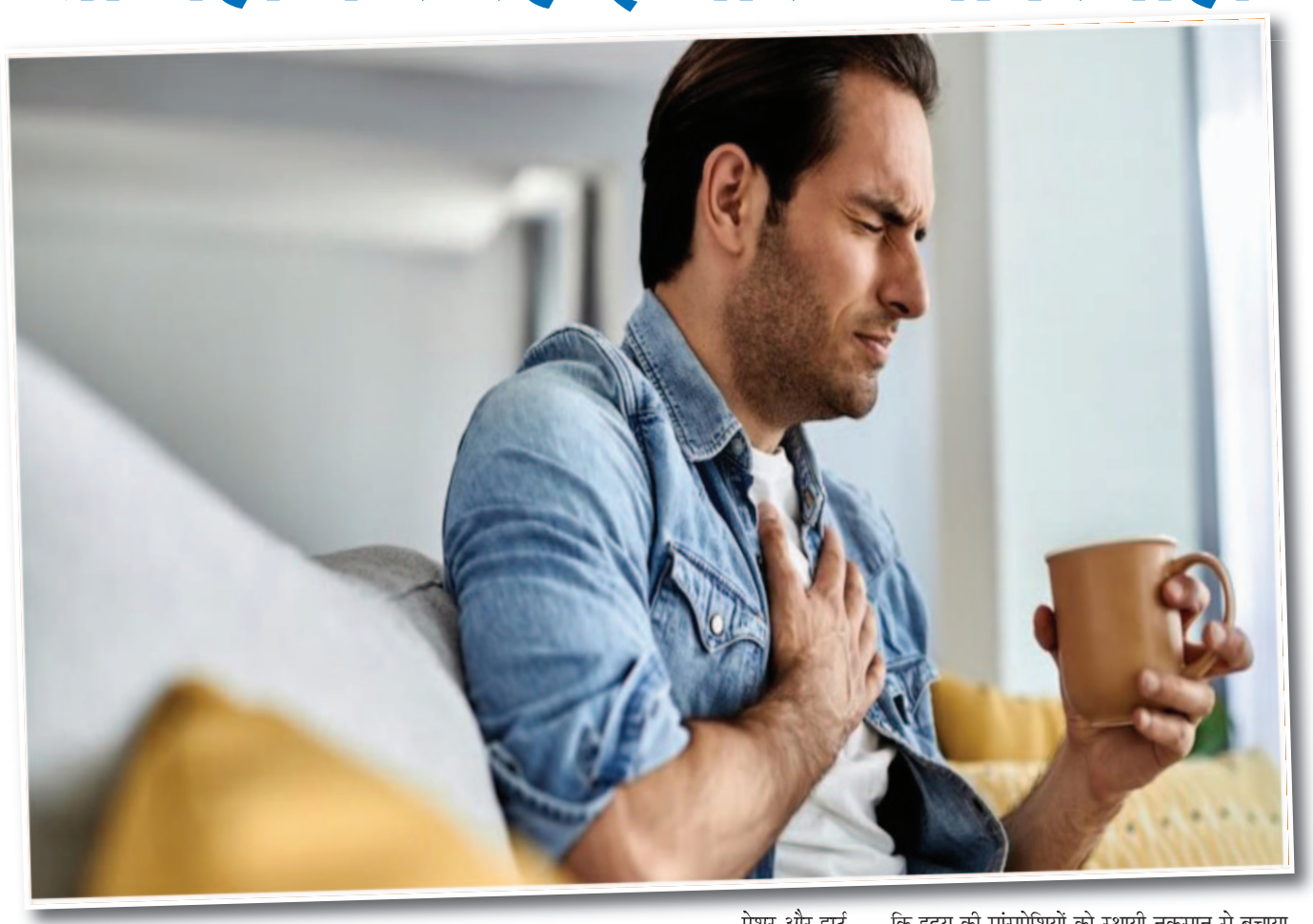

कुछ दशकों पहले तक हार्ट अटैक को उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्या के रूप में जाना जाता था, हालांकि कम उम्र के लोग भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। हाल के महीनों में आपने कई ऐसी खबरें देखी-सुनी होंगी, जिसमें 30 से कम उम्र के लोगों को न सिर्फ दिल का दौरा पड़ा बल्कि इससे कई लोगों की मौत भी हो गई।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, गड़बड़ जीवनशैली जैसे लंबे समय तक बैठकर काम करना, तनाव, खानपान में गड़बड़ी, धूम्रपान और मोटापा जैसी स्थितियों ने ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के खतरों को काफी बढ़ा दिया है। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि हार्ट अटैक के बाद अक्सर लोगों को समय रहते डॉक्टरी मदद नहीं मिल पाती है, इसके कारण भी खतरा बढ़ जाता है। समय पर हार्ट अटैक के संकेतों की पहचान न हो पाने को इसका बड़ा कारण माना जाता रहा है।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हार्ट अटैक के शुरुआती संकेतों को समय पर पहचानना जीवन बचाने में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि हृदय की मांसपेशियों को स्थायी नुकसान से बचाया जा सके।

हार्ट अटैक के असामान्य संकेतों को भी जानिए

डॉक्टर कहते हैं, हार्ट अटैक को अक्सर हम सभी सीने में तेज दर्द जैसे लक्षणों के साथ जोड़कर देखते हैं। सीने में दर्द, जकड़न और असहजता तो इसका संकेत है ही, पर इसके अलावा भी कई दिक्कतें हो सकती हैं जिसपर भी सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

हार्ट अटैक के कई संकेत पेट की दिक्कतों जैसे भी होते हैं। कई लोगों को गैस-एसिडिटी, बदहजमी जैसी दिक्कतें भी होती हैं जिसे सामान्य पेट दर्द समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है।

हार्ट अटैक में गोल्डन ऑवर सबसे महत्वपूर्ण

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के विशेषज्ञ जोर देते हैं कि हार्ट अटैक में गोल्डन ऑवर (पहला लगभग एक घंटा) बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान उपचार शुरू होने पर हृदय की मांसपेशियों को स्थायी नुकसान से काफी हद तक बचाया जा सकता है और मृत्यु का जोखिम कम होता है।

यदि मरीज पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग से पीड़ित है, तो ऐसे लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

बिना डॉक्टर की सलाह के केवल गैस या एसिडिटी की दवा लेकर इंतजार करना खतरनाक हो सकता है।

हार्ट अटैक में पाचन संबंधित दिक्कतें

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हार्ट अटैक की स्थिति में जब हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो शरीर कई तरह के संकेत देता है।
इससे सीने में दबाव, सांस फूलने, ठंडा पसीना आने, कमजोरी, जबड़े या हाथ में दर्द की दिक्कत होती है।
कई मरीजों में जी मिचलाने, उल्टी, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, भारीपन या जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों में ऐसे असामान्य लक्षण अधिक देखे जाते हैं।
इसलिए अगर पेट की परेशानी के साथ सीने में दबाव, सांस लेने में तकलीफ हो या चक्कर आए तो इसे केवल गैस समझकर दवा लेना खतरनाक हो सकता है। ऐसे समय में तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
हार्ट अटैक के दौरान हर मरीज में पेट दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में पेट से जुड़े लक्षण प्रमुख संकेत बन सकते हैं।
क्लीनिकल गाइडलाइंस के अनुसार, इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में मतली, उल्टी और पेट का दर्द अधिक देखा जाता है।

आंखों की थकान का कारण बन सकती है ज्यादा स्क्रीन टाइम

आज के समय में स्क्रीन टाइम का बढ़ता उपयोग आंखों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। चाहे वह कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो या टीवी, अधिक समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों की थकान हो सकती है। यह लेख आपको कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में बताएगा, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी आंखें थकी हुई हैं और आपको किन सावधानियों का पालन करना चाहिए।

आंखों की जलन और खुजली होना

अगर आपको स्क्रीन देखते समय आंखों में जलन या खुजली महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें अधिक समय तक स्क्रीन के सामने रहने के कारण थकी हुई हैं। इस स्थिति में तुरंत आंखों को आराम दें और उन्हें ठंडे पानी से धोएं या आंखों की बूंदों का उपयोग करें। इससे आपकी आंखों को राहत मिलेगी और वे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकेंगी, जिससे आपकी आंखों की थकान कम होगी।

सिरदर्द होना

अगर आपको स्क्रीन देखते समय सिरदर्द होता है तो यह भी एक सामान्य समस्या है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें और सिर एक-दूसरे पर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, जिससे दर्द होता है। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें। इससे सिरदर्द कम होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे।

आंखों का धुंधला दिखना

अगर आपको स्क्रीन देखते समय चीजें धुंधली दिखती हैं तो यह भी आंखों की थकान का संकेत हो सकता है। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी के कारण ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें। इससे आपकी आंखों की संवेदनशीलता कम होगी और आप बेहतर महसूस करेंगे।

लगातार झपकना

अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी आंखें बार-बार झपक रही हैं तो यह भी एक सामान्य संकेत हो सकता है। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी के कारण थकी हुई हैं। इस स्थिति में आंखों को आराम देना जरूरी है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से दूर रहें और आंखों को बंद करके कुछ मिनट आराम करें। इससे आपकी आंखों को राहत मिलेगी और वे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकेंगी।

आंखों का सूखना

अगर आप पाते हैं कि आपकी आंखें सूखी हो रही हैं तो यह भी आंखों की थकान का एक संकेत हो सकता है। यह लक्षण बताता है कि आपकी आंखें स्क्रीन की रोशनी के कारण ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। इस स्थिति में आंखों की बूंदों का उपयोग करें ताकि आपकी आंखें नमी बनी रहें।

17 जुलाई से रफ्तार भरेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, सभी स्टेशनों पर हुआ ट्रायल

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई से दौड़ने जा रही है। इसे स्वच्छ और भविष्य की रेल तकनीक की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इस ट्रेन का रूट क्या होगा और कितना किराया लगेगा?

भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने की तारीख सामने आ गई है। सरकार का दावा है कि इसके संचालन के दौरान लगभग शून्य प्रदूषण होगा। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। जींद-सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली इस ट्रेन के लिए जींद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा भी विकसित की गई है।

हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है? यह ट्रेन कैसे काम करेगी? जीवाश्म ईंधन-बिजली के मुकाबले ट्रेनों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कितना बेहतर है? ट्रेन का किराया और गति कितनी होगी? जींद-सोनीपत रूट को ही इसके संचालन के लिए क्यों चुना गया है? यह ट्रेन क्यों खास है? सुरक्षा के लिए इसमें क्या इंतजाम किए गए हैं? इस परियोजना पर कितना खर्च किया गया है? भारत के अलावा किन दशों में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन होता है? आइए विस्तार से जानते हैं...

इस परियोजना पर कितना खर्च किया गया है?

रेल मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के बजट में 2,800 करोड़ रुपये हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के विकास के लिए आवंटित किए थे।
इस राशि का उपयोग अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने में किया जा रहा है।
भारतीय रेलवे ने इसके अलावा मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) रैक में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाने की 111.83 करोड़ रुपये की पायलट परियोजना भी मंजूर की है।
रेलवे का कहना है कि फिलहाल हाइड्रोजन ट्रेनों की परिचालन लागत तय नहीं हुई है। शुरुआती चरण में इनका संचालन खर्च अधिक रहने का अनुमान है, लेकिन जैसे-जैसे ऐसी ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, लागत में कमी आने की उम्मीद है।

किस तकनीक पर काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन?

सीधे शब्दों में समझा जाए तो हाइड्रोजन ट्रेन उन ट्रेनों को कहा जाता है, जो कि संचालन के लिए बिजली या जीवाश्म ईंधन के बजाय हाइड्रोजन (H2) का इस्तेमाल करती हैं। इन ट्रेनों के इंजन को इस तरह बनाया जाता है कि इनमें ऊर्जा हाइड्रोजन के प्रयोग से पैदा की जाती है।

जीवाश्म ईंधन-बिजली के मुकाबले ट्रेनों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कितना बेहतर?

जीवाश्म ईंधन मुख्यतः कार्बन (C) आधारित होते हैं, इसलिए इनके प्रयोग से वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, जो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ग्लोबल वॉर्मिंग का मुख्य कारण है। इसे पर्यावरण के लिए घातक माना जाता है। इसलिए डीजल से चलने वाले इंजन सबसे बड़े प्रदूषकों में गिने जाते हैं। भारत में पहले ही इनका प्रयोग बहुत कम किया जा चुका है।

भारत में मौजूदा समय में बिजली का इस्तेमाल करके चलने वाली ट्रेनें प्रदूषण कम करने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, लेकिन इनके प्रयोग में एक पेंच यह है कि जिस बिजली से यह ट्रेनें चलती हैं, उसे फिलहाल ऐसे पावर स्टेशनों से पैदा किया जाता है जो कि कोयले (एक और जीवाश्म ईंधन) के प्रयोग से चलते हैं। ऐसे में बिजली से चलने वाली ट्रेनें खुद भले ही प्रदूषण का सीधे तौर पर कारण नहीं होतीं, लेकिन इन्हें मिलने वाली बिजली को जीवाश्म ईंधन से ही पैदा किया जाता है, जो कि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।

इसके चलते हाइड्रोजन के जरिए संचालित होने वाली ट्रेनें पर्यावरण के लिए काफी बेहतर होती हैं। यह ट्रेनें न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह बंद कर देती हैं, बल्कि आम ईंधनों के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा ऊर्जा देने वाली साबित होती हैं।

भारत की हाइड्रोजन ट्रेन में क्या है खास?

यह ट्रेन ब्रॉड गेज पर चलने वाली सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी।

इसमें कुल 10 कोच होंगे, जिनमें दो ड्राइविंग पावर कार और आठ यात्री कोच शामिल हैं।

इसकी कुल शक्ति 2400 किलोवाट होगी, यानी प्रत्येक ड्राइविंग पावर कार 1200 किलोवाट की क्षमता वाली होगी।

जींद-सोनीपत रेलखंड पर चलने वाली इस ट्रेन के लिए जींद में विशेष हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग सुविधा विकसित की गई है।

यहीं पर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को सुरक्षित रखा जाएगा और ट्रेन में भरा जाएगा।

रिफ्यूलिंग के लिए हाइड्रोजन कंप्रेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसके साथ आवश्यक तकनीकी-सहायता और महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि पूरी प्रणाली सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सके।

किसी तकनीकी खराबी की स्थिति में संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए स्टैंडबाय कंप्रेसर यूनिट की भी व्यवस्था की जा रही है।

सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

हाइड्रोजन गैस के सुरक्षित उपयोग के लिए रेलवे ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं।

हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और रिफ्यूलिंग स्टेशन पर हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर और फ्लेम डिटेक्टर लगाए गए हैं।

इन उपकरणों की नियमित जांच और सफाई की जाएगी ताकि धूल जमा न हो और वे लगातार सही तरीके से काम करते रहें।

पूरे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सिस्टम की 24 घंटे निगरानी की जाएगी।

शुरुआती चरण में ट्रेन के साथ तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके।

इसके अलावा ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट के लिए संचालन व रखरखाव मैनुअल तैयार किए गए हैं, जिन्हें आरडीएसओ (RDSO) से मंजूरी मिल चुकी है।

शकूरबस्ती स्थित रखरखाव केंद्र के लिए भी सुरक्षा प्रावधान, नियमित ऑडिट और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की गई है।

जींद-सोनीपत पर चलने वाली ट्रेन के बारे में जानें सबकुछ

यह ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

इस रूट पर यात्रा का अनुमानित समय करीब एक घंटा होगा।

शुरुआती ट्रायल के दौरान ट्रेन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।

भविष्य में इसकी अधिकतम गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक प्रस्तावित है।

इस रूट पर कुल छह रेलवे स्टेशन होंगे।

ट्रेन का न्यूनतम किराया 5 रुपये और अधिकतम किराया 25 रुपये प्रस्तावित है।

इस ट्रेन में करीब 2,500 यात्रियों के सफर कर सकते हैं।

जींद-सोनीपत रूट को क्यों चुना गया?

इस रूट को पायलट प्रोजेक्ट इसलिए चुना गया है क्योंकि भारतीय रेलवे का ज्यादातर ब्रॉड गेज नेटवर्क पहले ही बिजली से जुड़ चुका है।

अब रेलवे हाइड्रोजन तकनीक का परीक्षण उन इलाकों के लिए कर रहा है, जहां बिजली के ओवरहेड तार बिछाना मुश्किल या बहुत महंगा पड़ता है।

जींद में पहले से हाइड्रोजन प्लांट है, इसलिए ट्रेन को हाइड्रोजन ईंधन आसानी से मिल सकेगा।

यह रूट छोटा है और यहां ट्रेन की गति भी कम रहती है, इसलिए नई तकनीक का सुरक्षित परीक्षण करने के लिए यह उपयुक्त है।

हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना क्या है?

भारतीय रेलवे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना के तहत कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इन ट्रेनों को मुख्य रूप से हेरिटेज और पहाड़ी रेल मार्गों पर चलाने की योजना है ताकि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण कम हो और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

इस योजना के तहत एक हाइड्रोजन ट्रेन की अनुमानित लागत लगभग 80 करोड़ रुपये है, जबकि प्रत्येक रूट पर आवश्यक हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की लागत लगभग 70 करोड़ रुपये आंकी गई है।

..और किन देशों में हो रहा हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन?

चीन: यहां हाइड्रोजन से चलने वाली कम्यूटर (शहरी) और पर्यटन के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
जापान: जापान ने त्सुरुमी लाइन सहित कई मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों का सफल परीक्षण किया है।
अमेरिका: दक्षिणी कैलिफोर्निया में 'एरो' नाम की हाइड्रोजन कम्यूटर ट्रेन संचालित की जा रही है।
फ्रांस और स्वीडन: दोनों देश भी हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक के विकास और पायलट परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।
ब्रिटेन: ब्रिटेन में हाइड्रोजन ट्रेनों का अलग से उत्पादन नहीं किया गया है, बल्कि यहां पहले से जीवाश्म ईंधन या बिजली पर चल रही ट्रेनों में ही हाइड्रोजन टैंक और फ्यूल सेल लगाए गए।
जर्मनी: दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में 2016 में उतारी गई थी। 2018 में इस ट्रेन का वाणिज्यिक स्तर पर संचालन शुरू किया गया। तबसे लेकर अब तक जर्मन कंपनी एलस्टोम कोरैडिया आईलिंट अलग-अलग मार्गों पर इन ट्रेनों को चला रहा है।
स्विट्जरलैंड: 2022 में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन के मॉडल को पेश किया गया था। अगले एक साल में स्विट्जरलैंड की अधिकतर ट्रेनों में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया।

महंगे हुए टीवी, फ्रिज और स्मार्टफोन, फिर भी जबरदस्त खरीदारी! 90 दिन में लोन का बना नया रिकॉर्ड

जून तिमाही में कंज्यूमर फाइनेंसिंग ने नया रिकॉर्ड बनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज्यादा फाइनेंसिंग और बढ़ती कीमतों की वजह से इसमें तेजी आई। बैंकों और NBFCs ने कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखी। अब स्मार्टफोन की सेल्स में फाइनेंसिंग का हिस्सा काफी बढ़ गया है। फाइनेंसिंग की लंबी अवधि से ग्राहकों के लिए मासिक किस्तें (EMI) सस्ती बनी रहती हैं।

जहां एक ओर बीते कुछ महीनों में टीवी, फ्रिज और स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर इन सामानों की खरीदारी में भी इजाफा देखने को मिला है। जिसकी वजह से जून तिमाही में कंज्यूमर फाइनेंसिंग में एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), मार्केट रिसर्च करने वाली कंपनियों और दूसरी कंपनियों के डाटा से पता चलता है कि इससे कुल रिटेल सेल्स में इसकी हिस्सेदारी बढ़ी। वास्तव में कंज्यूमर्स ने कीमतों में भारी बढ़ोतरी और आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए ज्यादा लोन लिए।

रिपोर्ट के अनुसार इस बढ़ोतरी की वजह स्मार्टफोन, टेलीविजन, लैपटॉप और एयर-कंडीशनर जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज्यादा फाइनेंसिंग थी। इन चीजों की कीमतें कंपनियों ने पिछले छह महीनों में 12-40 फीसदी तक बढ़ाई थीं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वेस्ट एशिया संकट की वजह से बढ़ी कमोडिटी की लागत और मेमोरी चिप की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की भरपाई की जा सके।

कंज्यूमर लोन में इजाफा

ईटी की रिपोर्ट में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इक्विफैक्स इंडिया के डाटा हवाला दिया गया है। जिसमें कहा गयर है कि इस फाइनेंशियल ईयर में मई तक बैंकों और नॉन-बैंक फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) से कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का बकाया 9।2 फीसदी बढ़कर 1।19 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो मार्च तक 1।09 लाख करोड़ रुपए था। RBI के ताजा डाटा से पता चलता है कि मई के आखिर में बैंकों का कंज्यूमर लोन बकाया मार्च के मुकाबले 4।3 फीसदी बढ़कर 22,906 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2026 में 5।3 फीसदी की गिरावट के बाद रिकवरी थी।

मई के आखिर में बैंकों का क्रेडिट कार्ड बकाया सालाना आधार पर 1।3 फीसदी बढ़कर 2।95 लाख करोड़ रुपए हो गया, हालांकि यह मार्च के मुकाबले लगभग उतना ही रहा। जून का डेटा अभी आना बाकी है। सेंट्रल बैंक ने मंगलवार को कहा कि मई के आखिर में वित्त वर्ष 2027 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों समेत ऊपरी और मिड-टियर NBFCs के कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन सालाना आधार पर 42 फीसदी बढ़कर 68,814 करोड़ रुपए हो गए। यह डाटा एनबीएफसी सेक्टर के 87 फीसदी हिस्से को कवर करता है।

कड़े किए नियम

इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन विजय सेल्स के डायरेक्टर नीलेश गुप्ता ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि इस साल एवरेज फाइनेंसिंग का समय लगभग तीन महीने बढ़ गया है। हालांकि कंज्यूमर फाइनेंस अब छोटे शहरों तक फैल गया है, लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि कुछ कंज्यूमर्स को मंजूरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि NBFCs ने अपने लोन देने के नियम कड़े कर दिए हैं। यह ट्रेंड लेंडर्स में भी दिखा। भारत की सबसे बड़ी NBFC, बजाज फाइनेंस ने जून तिमाही में 16।4 मिलियन लोन बांटे, जो त्योहारों वाली दिसंबर तिमाही के 13।9 मिलियन से ज़्यादा थे। नए लोन की संख्या सालाना आधार पर 22 फीसदी बढ़ी। इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि NBFCs का छोटे शहरों में विस्तार कंज्यूमर फाइनेंसिंग में भी तेजी ला रहा है, जो पहले बैंकों का दबदबा वाला सेक्टर था।

प्रेशर में स्मार्टफोन मार्केट

स्मार्टफोन मार्केट रिसर्चर 'काउंटरपॉइंट रिसर्च' के अनुसार, जून तिमाही में स्मार्टफोन की कुल बिक्री में लगभग 11 फीसदी की गिरावट के बावजूद, फाइनेंसिंग के जरिए हुई बिक्री का हिस्सा 35 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी हो गया। काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक ने रिपोर्ट में कहा कि स्मार्टफोन मार्केट प्रेशर में है और इसके और बढ़ने की उम्मीद है, ऐसे में फाइनेंसिंग खरीदारी का मुख्य जरिया बनकर उभर रही है। अब फाइनेंसिंग के जरिए बिकने वाले लगभग 67 फीसदी स्मार्टफोन NBFCs के जरिए फाइनेंस किए जाते हैं।

क्रेडिट से पेमेंट करने का चलन बढ़ा

ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कैलाश लखयानी ने कहा कि जनरल ट्रेड में फाइनेंसिंग बढ़ी है। जून तिमाही में इसमें साल-दर-साल 20-23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह कैश के बजाय क्रेडिट से पेमेंट करने का चलन है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स ने मंथली किस्तों को किफायती बनाए रखने के लिए फाइनेंसिंग की अवधि बढ़ा दी है। स्मार्टफोन फाइनेंसिंग की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई है, जबकि टीवी, लैपटॉप, AC और रेफ्रिजरेटर के लिए फाइनेंसिंग की अवधि 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है।

मानसून ने बढ़ाई माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की धड़कनें! संकट में आया ₹3 लाख करोड़ का कर्ज

भारतीय माइक्रोफाइनेंस लेंडर्स (कर्ज देने वाली संस्थाएं) के पोर्टफोलियो पर फिर से दबाव बढ़ रहा है। कीमतों के दबाव और कमजोर मज़नसून से रूरल इनकम पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे इंडस्ट्री के 35 अरब डॉलर के लोन बुक में डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेक्टर की लीड, गीता चुघ ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि कमजोर मानसून से लोन ग्रोथ धीमी हो सकती है। इसका कारण भी है। लेंडर्स अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को सख्त कर रहे हैं और कर्ज लेने वालों की कर्ज चुकाने की क्षमता घट रही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग 20 फीसदी माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों ने दो से अधिक लेंडर्स से लोन लिया है। उन्होंने कहा कि इस सेगमेंट में, कम लेंडर्स से जुड़े कर्जदारों की तुलना में डिफॉल्ट की दर (डेलिंक्वेंसी रेट) काफी अधिक देखी जा रही है।

लगातार दबाव में थे लेंडर्स

इस सेक्टर में बंधन बैंक लिमिटेड और क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, सैटिन क्रेडिटकेयर नेटवर्क लिमिटेड और मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड जैसी नॉन-बैंक कंपनियों का काफी एक्सपोजर है। मार्च के अंत में बंधन बैंक के कुल लोन बुक में माइक्रोफाइनेंस और माइक्रो-लेंडिंग सेक्टर के लोन का हिस्सा 23 फीसदी देखने को मिला था। पिछले दो वर्षों से माइक्रोफाइनेंस सेक्टर दबाव में था। तेजी से क्रेडिट विस्तार के कारण कई कर्जदार कर्ज के बोझ तले दब गए थे, जिससे डिफॉल्ट बढ़े और लेंडर्स को अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स सख्त करने पड़े। हालांकि, हालात अब स्थिर होने लगे हैं क्योंकि लेंडर्स ने इंडस्ट्री बॉडी के दिशा-निर्देशों के बाद कर्जदारों के कर्ज के बोझ को कम करने और कुल पोर्टफोलियो जोखिम को सीमित करने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।

मानसून बनकर आया विलेन

सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार सात तिमाहियों तक गिरावट के बाद जनवरी-मार्च में बकाया माइक्रोफाइनेंस क्रेडिट में बढ़ोतरी हुई, जिससे कंपनियों के शेयर की कीमतों को सहारा मिला। अब इस रिकवरी के सामने नए जोखिम हैं। 12 वर्षों में सबसे सूखा जून देखने के बाद, भारत में जुलाई – मानसून सीजन का मुख्य महीना – में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। कम बारिश से फसल उत्पादन और कृषि आय पर बुरा असर पड़ता है, जिससे ग्रामीण परिवारों की खर्च करने और कर्ज चुकाने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही, मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण फ्यूल ईंधन, खाद और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ सकती है, जिससे कम आय वाले कर्जदारों पर और दबाव पड़ सकता है।

कृषि और उससे जुड़े लोन

चुघ ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस लेंडर्स का लगभग 80 फीसदी एक्सपोजर ग्रामीण इलाकों में होता है, जिसमें 35 फीसदी लोन सीधे कृषि से, 9 फीसदी कृषि-आधारित उद्यमों से और 20 फीसदी पशुपालन से जुड़े होते हैं। सेंट्रल बैंक ने जून में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालांकि अधिकांश सेक्टर में क्रेडिट क्वालिटी में सुधार हुआ है, लेकिन खेती के क्षेत्र में सुधार धीमा रहा और वहां सबसे अधिक नॉन-परफॉर्मिंग लोन (NPL) देखे गए। चुघ ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट के असर और कमजोर मानसून, दोनों ही मैक्रो-लेवल की चुनौतियां हैं जो महंगाई को बढ़ाएंगी और लेंडर इस सेक्टर को लेकर सतर्क रहेंगे। अगर महंगाई बनी रहती है, तो इससे कर्ज लेने वालों की कर्ज चुकाने की क्षमता और कम हो सकती है और ये जोखिम और बढ़ सकते हैं।

निज्जर हत्याकांड : भारतीय अधिकारियों के खिलाफ नहीं मिला सबूत, दुनिया को झूठ बताते रहे जस्टिन ट्रूडो

कनाडा, एजेंसी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में साल 2023 में हुई खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने अपने बयान में कहा है कि निज्जर हत्याकांड में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस हत्या में भारत सरकार या उसके किसी भी अधिकारी का कोई संबंध नहीं है। दरअसल साल 2023 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने दावा किया था कि इस हत्या के पीछे भारतीय एजेंटों की भूमिका हो सकती है। उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के के बीच तल्खी बढ़ गई थी। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था और कनाडा से सबूत पेश करने को कहा था। वहीं अब मीडिया से बात करते हुए RCMP की डिप्टी कमिश्नर लीसा मोरलैंड ने कहा कि निज्जर हत्याकांड मामले की जांच के दौरान भारत सरकार या भारतीय अधिकारियों को इस मामले से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा जिस संगठित अपराध नेटवर्क की जांच की जा रही है उसमें भारतीय सरकारी अधिकारियों के शामिल होने के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निज्जर हत्या की अलग जांच अभी जारी है ऐसे में उस पर विस्तृत टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लीसा मोरलैंड का बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ निज्जर की हत्या के आरोप तय किए हैं। अमेरिका के लॉस एंजिलिस में दायर संघीय अभियोग के मुताबिक 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे स्थित एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कराने का आदेश बिश्नोई और बराड़ ने दिया था। अभियोग में दावा किया गया है कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई तस्करी से पहुंचाए गए मोबाइल फोन के जरिए पूरे ऑपरेशन का संचालन कर रहा था, उसने एक सह-साजिशकर्ता को निज्जर की तस्वीर और उसके कई पते भी उपलब्ध कराए थे ताकि हत्या को अंजाम दिया जा सके। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' के तहत यह साफ हो गया है कि निज्जर की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ था। निज्जर की हत्या 18 जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे की पार्किंग में हुई थी। दो नकाबपोश हमलावरों ने उसकी कार के पास गोली मारकर हत्या कर दी थी।स घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें 2 नकाबपोश हमलावर उस पर गोलीबारी करते दिखाई दिए थे।

पंजाब का दरोगा अमेरिकी परिवार से कर रहा था वसूली, गोल्डी बराड़ के साथ वॉन्टेड के पोस्टर में छपी फोटो

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के अधिकारियों ने पंजाब के दारोगा गुरिंदरजीत सिंह पर एक अमेरिकी परिवार से 4 लाख डॉलर (करीब 4 करोड़ भारतीय रुपए) रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया है। एफबीआई का कहना है कि गुरिंदरजीत सिंह लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक शख्स परिवार से 4 लाख डॉलर की मांग की। गुरिंदरजीत ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो पंजाब में रहने वाले उनके रिश्तेदारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा किया जाएगा। एफबीआई के इस आरोप पर पंजाब पुलिस ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम मजीठिया के मुताबिक गुरिंदरजीत सिंह का पूरा नाम गुरिंदरजीत सिंह नागरा है। यह मामला गुरिंदरजीत के होशियारपुर जिले के टांडा में थाना प्रभारी रहने के दौरान का है। मजीठिया का कहना है कि गुरिंदरजीत ने रंगदारी न देने पर अमेरिकी परिवार के रिश्तेदारों को हत्या के एक मामले में कथित तौर पर नामजद कर दिया। वहीं अमेरिका के संघीय अधिकारियों का कहना है कि गुरिंदरजीत सिंह ने जगगु भगवानपुरिया नामक संगठित अपराध समूह के सदस्यों के साथ मिलकर अपराध की घटना को अंजाम दिया।

दारोगा गुरिंजरजीत सिंह का नाम कैसे आया?

कुछ महीने पहले अमेरिकी अधिकारियों ने जग्गु गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। यह सदस्य अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा था। जब उक्त शख्स से पूछताछ हुई, तो उसने दारोगा गुरिंदरजीत सिंह का नाम उगल दिया। इसके बाद अधिकारियों ने जांच के दायरे को आगे बढ़ाया।

जांच के दौरान पता चला कि अमेरिकी पुलिस ने लॉस एंजिल्स में एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा है, उसकी जानकारी किसी तरह गुरिंदरजीत सिंह को मिल गई। उसने यहां पर उसके परिवार से केस सेटल के नाम पर पैसा वसूलने की कवायद शुरू कर दी।

अब अमेरिकी अधिकारियों ने अपने हिट लिस्ट में दारोगा गुरिंदरजीत सिंह को शामिल किया है। गुरिंदरजीत सिंह की तस्वीर गोल्डी बराड़ वाले पोस्टर पर छापी गई है। वहीं पूरे मामले में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए दारोगा गुरिंदरजीत सिंह ने इस मामले से खुद को पाक-साफ बताया है। गुरिंदरजीत सिंह का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है।

AI तकनीक लीक हुई तो खैर नहीं... अपनी ही कंपनियों को चीन की चेतावनी का क्या मकसद

बीजिंग, एजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के अधिक से अधिक और सही इस्तेमाल को लेकर ज्यादातर देशों में हलचल बनी हुई है। चीन भी इस दिशा में लगातार और तेजी से काम कर रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी एडवांस्ड AI तकनीक और मॉडल के लीक होने या चोरी होने से बचाना है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीनी अधिकारियों ने पिछले महीने बड़ी टेक कंपनियों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। बैठकों में चीन के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल को अपने ही देश में रोके रखने को लेकर मंथन किया गया। कोशिश यही है कि यह एडवांस्ड तकनीक विदेश जाने न पाए। हालांकि एडवांस्ड AI मॉडल को अभी रिलीज नहीं किया गया है। बातचीत की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि चीनी अधिकारियों ने चीन के सबसे एडवांस्ड AI मॉडल को लीक होने से रोकने को लेकर टेक

कंपनियों से गंभीर बैठक की है। ये बातचीत बीजिंग द्वारा घरेलू AI को देश के भीतर ही रखने के लिए उठाए गए कई कदमों के बाद हुई है।

इससे यह पता चलता है कि अमेरिका की तरह चीन भी अब अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक अहम राष्ट्रीय संपत्ति मानता है जिस पर वह नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। इन लोगों ने बताया कि बातचीत में शामिल कंपनियों में टेक दिग्गज अलीबाबा और बाइटडांस (ByteDance) के साथ-साथ स्टार्टअप Z lai भी शामिल थे। स्थिति यह थी कि इन लोगों को मीडिया से बात करने की इजाजत तक नहीं थी और उन्होंने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। पिछले साल डीपसीक के R1 मॉडल के आने के बाद से, चीनी AI मॉडल्स अपनी कम लागत और बढ़ती क्षमताओं की वजह से पूरी दुनिया में तेजी से फैलते जा रहे हैं। अगर बीजिंग इन प्रोडक्ट्स तक पहुंच सीमित करने को लेकर कोई फैसला करता है, तो इसका असर AI बाजार पर खासा असर पड़ने की संभावना है क्योंकि कई बिजनेस के लिए लागत बढ़ सकती है।

AI चोरी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान!

मामले से जुड़े 2 सूत्रों के अनुसार, चीन के वाणिज्य मंत्रालय की अगुवाई में हुई इन बैठकों में सबसे एडवांस्ड AI मॉडल (क्लोज्ड-सोर्स और ज्यादा ओपन वर्जन) दोनों पर कंट्रोल लगाने को लेकर चर्चा की गई। एक सूत्र ने बताया कि अधिकारियों ने प्रोप्राइटरी AI टेक्नोलॉजी के किसी भी लीक या चोरी को लेकर चीन में कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपराध की श्रेणी में लाए जाने की बात हुई है। सूत्र ने आगे बताया कि अधिकारियों ने घरेलू AI स्टार्टअप को कौन फंड दे सकता है, इस पर रोक लगाने के लिए नए उपाय लाने की संभावना पर भी चर्चा की गई। 2 सूत्रों ने कहा कि संभावित प्रतिबंधों के दायरे को लेकर चर्चा चल रही है और हो सकता है कि ये केवल भविष्य के मॉडल पर लागू किए जाएं। हालांकि यह तुरंत साफ नहीं हो सका है कि ये कब लागू होंगे या लागू होंगे भी या नहीं।

अलीबाबा- बाइटडांस की कैसी प्रतिक्रिया

चीन का वाणिज्य मंत्रालय, जो निर्यात से जुड़े नियमों की देखरेख करता है, और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन- देश की सरकारी योजना एजेंसी जिसके अधिकारियों ने भी बैठकों में भाग लिया था, लेकिन रॉयटर्स की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया।

साथ ही अलीबाबा, बाइटडांस और Z lai कंपनियों ने भी रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों कंपनियों के पास कई AI मॉडल्स हैं। इनमें से कुछ क्लोज्ड-सोर्स हैं तो कुछ ओपन-वेट हैं, जिसका मतलब यह है कि यूजर इनके अंदर के सिस्टम को डाउनलोड, रन और कस्टमाइज कर सकते हैं। अलीबाबा का Qwen और बाइटडांस का Doubao चीन में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले AI मॉडल्स हैं। हाल ही में Z lai ने सिलिकॉन वैली में जबर्दस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि इसके GLM-5।2 मॉडल की क्षमताएं अमेरिका के टॉप मॉडल्स के बराबर हैं, जबकि इसकी लागत बहुत कम है।

AI मॉडल और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन AI से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर भी बहुत अधिक चिंतित है। खासकर इस बात को लेकर कि अमेरिकी AI प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल चीन, रूस और कई अन्य देशों की मिलिट्री इंटेलिजेंस की ओर से किया जा सकता है। जून में, सरकार ने आदेश दिया कि विदेशी नागरिकों को एंथ्रोपिक (Anthropic) के सबसे एडवांस्ड Fable और Mythos मॉडल का एक्सेस न दिया जाए। इसके बाद कंपनी ने दुनिया भर के सभी यूजर्स के लिए इन मॉडल्स की सप्लाई को बंद कर दिया, क्योंकि रियल टाइम में किसी की नेशनैलिटी की पुष्टि नहीं की जा सकती थी। यहां तक आम जनता के लिए बनाए गए Fable पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी हटा दिया गया, क्योंकि अब इस पर नए सुरक्षा उपाय लागू कर दिए गए हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया Mythos अभी भी सिर्फ कुछ "भरोसेमंद" अमेरिकी संगठनों के लिए ही उपलब्ध है। अमेरिका के कुछ AI एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि अमेरिका को चीनी AI मॉडल्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की जरूरत है।

Mythos के खतरे को लेकर चीन में चिंता

मामले से जुड़े 2 सूत्रों के अनुसार, चीनी अधिकारी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि Mythos सॉफ्टवेयर की कमियों का फायदा उठा सकता है और वाशिंगटन इस मॉडल का इस्तेमाल चीन के हितों के खिलाफ कर सकता है। इस मामले में सरकारी मीडिया और साइबर सिक्योरिटी फर्म 360 के फाउंडर झोउ होंगयी ने भी सार्वजनिक रूप से चिंता जताई है। 360 नाम की कंपनी सरकारी और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सर्विस देने वाली एक बड़ी कंपनी है, और झोउ का कहना है कि चीन को अपना खुद का Mythos विकसित करने की जरूरत है।

चीन में लोकल AI स्टार्टअप्स की जांच शुरू?

इस बीच चीन ने इस साल अपने देश में बने AI को सुरक्षित रखने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। अप्रैल में, देश की सरकारी प्लानिंग एजेंसी ने मेटा (Meta) को आदेश दिया कि वह चीनी मूल के AI स्टार्टअप Manus के 2 अरब डॉलर के अधिग्रहण को रद्द करे। पिछले महीने जून की शुरुआत में, अधिकारियों ने नए और कड़े नियम लागू कर दिए, जिनसे चीनी इन्वेस्टर्स, टेक्नोलॉजी, डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विदेशी सौदों पर कंट्रोल और सख्त हो गया। 2 सूत्रों और एक तीसरे व्यक्ति के अनुसार, चीन ने इस साल मैनस और विदेश चली गई दूसरी लोकल AI स्टार्टअप्स की जांच शुरू कर दी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल कानूनों का किसी तरह से उल्लंघन किया है। हालांकि मैनस ने भी इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है।

ई20 पेट्रोल पर छिड़ी रार, कल जनता के बीच जाएंगे केजरीवाल, 29 कंपनियों को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली, एजेंसी। देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर में जनता के बीच जाएंगे। वो इस 20 प्रतिशत एथनॉल वाले पेट्रोल पर जनता से राय लेंगे। केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि कल मैंने कहा था कि देश के सभी वहन निर्माताओं को चिट्ठी लिखकर पूछूंगा कि क्या उनके पुराने वाहनों में E20 ईंधन का इस्तेमाल किया जा सकता है? नुकसान होता है या नहीं?

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने तीन कंपनियों मारूति, टॉयोटा और हिरो को अलग से चिट्ठी लिखी है और 26 को अलग। इन तीनों ने सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नुकसान नहीं होता, 3-4 फीसदी ही माइलेज का नुकसान होता है तो इनसे पूछा है कि अगर किसी ग्राहक का 10-15 फीसदी माइलेज घटता है या इंजन को नुकसान पहुंचता है तो उसे कवर करेंगे? बाकी 26 वाहन निर्माता कंपनियों से पूछा है कि क्या आपकी गाड़ियों में E-20 पेट्रोल से माइलेज या इंजन का नुकसान तो नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उनको कौन कंपनसेशन देगा? E20 फ्यूल पर विवाद इस बात को लेकर है कि 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां E10 के लिए बनी हैं। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 भरने के बाद गाड़ी की माइलेज 2-6% तक घट गई है। मतलब एक लीटर पेट्रोल से पहले जितना रन नहीं मिल रहा। E20 में ज्यादा एथनॉल होने से रबर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ARAI की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। हालांकि, यह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उधर, सरकार का कहना है कि अब तक किसी गाड़ी में बड़ी खराबी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर कई गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एथनॉल मिश्रित ईंधन के कारण एक भी कार में कोई समस्या नहीं आई है।

कलकत्ता हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

क्या पत्नी का पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगना भी दहेज? अदालत ने किया स्पष्ट

मुंबई, एजेंसी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति के दबाव में पैतृक संपत्ति में अपने वैध हिस्से की मांग करती है, तो यह दहेज की मांग के बराबर हो सकती है। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्वा सिन्हा राय की खंडपीठ ने दहेज हत्या के मामले में पति की सजा के खिलाफ अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। 2 जुलाई के फैसले में न्यायालय ने कहा कि एक महिला पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करने की कानूनी रूप से हकदार है, लेकिन अगर यह दावा पति के दबाव के कारण किया जाता है तो यह दहेज की मांग के दायरे में आएगा। यह मामला एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी की मौत से जुड़ा है, जो जून 2014 में, महिला की शादी के लगभग चार साल बाद, वैवाहिक घर में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थीं। निचली अदालत ने पाया कि महिला ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या करने से पहले अपनी बेटी की भी हत्या कर दी थी। अदालत ने पति और उसके माता-पिता को क्रूरता और दहेज हत्या का दोषी पाया। पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं, सास-ससुर को सात साल की कैद की सजा दी गई।

आरोपी पति ने क्या तर्क दिया?

उच्च न्यायालय के समक्ष पति ने यह तर्क दिया कि दहेज की मांग का कोई सबूत नहीं था। महिला ने केवल अपनी पैतृक संपत्ति में अपना कानूनी हिस्सा मांगा था। हालांकि, अदालत ने गौर किया कि सबूतों से पता चलता है कि महिला के भाई ने पहले परिवार की पुश्तैनी संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचकर उसे बिक्री से मिले राशि में से उसका हिस्सा दे दिया था।

दहेज की मांग कब होती है?

अदालत ने पाया कि इसके बाद भी पति लगातार महिला पर दबाव डालता रहा कि वह अपने भाई से बाकी पुश्तैनी संपत्ति बेचने और उसके हिस्से की राशि सौंपने के लिए कहे। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर होता है। न्यायालय ने कहा कि दहेज की मांग आमतौर पर वैवाहिक घर की चारदीवारी के भीतर ही की जाती है, न कि बाहरी लोगों की उपस्थिति में।

पति ने यह भी तर्क दिया था कि घटना के दो दिन बाद दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) अविश्वसनीय थी क्योंकि शिकायतकर्ता (मृत महिला के बड़े भाई) ने इसे दर्ज करने से पहले वकीलों से सलाह ली थी। इस दलील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं होता है।

एफआईआर दर्ज करने में देरी पर कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायालय ने कहा 'जब किसी की बहन और उसके नवजात शिशु की अचानक मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है, तो इससे करीबी रिश्तेदार स्तब्ध और अवाक रह जाते हैं। वे अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। हमारी राय में, इस तरह की देरी अभियोजन पक्ष के मामले को कोई झटका नहीं दे सकती। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में कानूनी सलाह लेना वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से सबसे तर्कसंगत कदम है।

हालांकि, अदालत को सास-ससुर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, क्योंकि शिकायतकर्ता ने मुकदमे के दौरान उन्हें दोषी नहीं ठहराया और किसी अन्य गवाह ने विशेष रूप से उन्हें कोई भूमिका नहीं सौंपी। न्यायालय ने सास-ससुर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वहीं, पति की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304बी (दहेज हत्या) के तहत आजीवन कारावास का प्रावधान दुर्लभ मामलों के लिए ही होना चाहिए।

आर माधवन बने भारत के एडिसन जी डी नायडू, नई फिल्म जीडीएन का दमदार ट्रेलर हुआ जारी, मिला जोरदार रिस्पॉन्स

पैन इंडिया स्टार आर माधवन अब तक बड़े पर्दे पर कई तरह की भूमिकाएं निभा चुके हैं और हर किरदार के साथ उन्होंने न्याय किया है। माधवन ने सिर्फ रोमांस या कॉमेडी ही नहीं एक्शन और बायोपिक में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। पिछले दिनों आदित्य धर की धुरंधर में अजय सान्याल की भूमिका से उन्होंने वाहवाही लूटी और अब वह भारत के एडिसन कहे जाने वाले दूरदर्शी आविष्कारक गोपालास्वामी दोरईस्वामी नायडू यानी जीडी नायडू का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। जी हां, आर माधवन की अपकमिंग फिल्म जीडीएन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें माधवन जीडी नायडू के किरदार में नजर आ रहे हैं और इस ट्रेलर को ऑडियंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन अभिनेता के कुछ फैन इस बात को लेकर निराश हैं कि मेकर्स ने फिल्म का हिंदी ट्रेलर जारी नहीं किया गया है। और पूछ रहे हैं कि हिंदी ट्रेलर कब जारी किया जाएगा।

जीडीएन के ट्रेलर की शुरुआत जीडी नायडू के किरदार के साथ होती है और आर माधवन एक दमदार और प्रभावशाली अवतार में नजर आ रहे हैं। जीडीएन में माधवन भारतीय तकनीकी पुनर्रचनाकार और औद्योगिक क्षेत्र के अग्रणी जी.डी. नायडू के व्यक्तित्व को पर्दे पर जीवंत करते दिखाई देते हैं और इस किरदार में पूरी तरह ढले हुए लग नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि कैसे बूढ़े जीडी नायडू अपने ही घर को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। मिलियन्स में कमाई और अंग्रेजों के जमाने में काम। उस दौर में उन्होंने कई जरूरी चीजों का आविष्कार किया, जिनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। मगर एक समय उन पर जर्मनी के नाजी हिटलर के साथ काम करने का आरोप लगा, जिसके बाद से नायडू की मुश्किलें बढ़ने लगीं। मगर, उन्होंने हार नहीं मानी और आविष्कार करते रहे।

जीडीएन का ट्रेलर शेयर करते हुए माधवन ने कैप्शन में लिखा जीडीएन। वहीं फिल्म की रिलीज की बात करें तो ये 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। माधवन इससे पहले जीनियस साइंटिस्ट नम्बी नारायण की बायोपिक रॉकेट्री में साइंटिस्ट की भूमिका निभा चुके हैं और इस किरदार में उन्हें काफी पसंद किया गया था। ऐसे में दर्शक उन्हें एक बार फिर देश के एक बड़े आविष्कारक की भूमिका में देखने को बेताब हैं। इस अपकमिंग बायोग्राफी में आर माधवन के साथ प्रियामणि, जयराम और सत्यराज जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

जीडीएन के ट्रेलर को दर्शकों से भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई ने तो ये तक दावा कर दिया कि माधवन एक बार फिर नेशनल अवॉर्ड जीनते की तैयारी में हैं। वहीं कई का कहना है कि वह न सिर्फ इस दूरदर्शी इनोवेटर की जिंदगी को दिखाते नजर आएंगे, बल्कि उनके सफर के पीछे की भावनात्मक और बौद्धिक ताकत को भी दर्शकों के सामने रखते नजर आएंगे। एक ने ट्रेलर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आर माधवन जीडीएन में बेहद असरदार और जमीन से जुड़े लग रहे हैं। फैंस का कहना है कि वह जीडी नायडू के रोल में एक्टिंग करते हुए नहीं दिखते, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह ही जीडी नायडू हैं।

फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया रोमांटिक गाना तुम ही से प्यार रिलीज, जुबिन नौटियाल ने दी आवाज

निर्देशक मिलाप जावेरी की फिल्म तेरा यार हूं मैं काफी वक्त से लोगों का ध्यान खींच रही है। इस फिल्म से अमन इंद्र कुमार बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, जो धमाल 4 के निर्देशक इंद्र कुमार के बेटे हैं। उनके साथ मुख्य किरदार में आकांक्षा शर्मा दिखाई देंगी। अब निर्माताओं ने फिल्म से रोमांटिक और दर्दभरा गाना तुम ही से प्यार जारी किया है, जिसमें अमन और आकांक्षा की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही है।

पिछले महीने निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल ट्रैक जारी किया था। अब तुम ही से प्यार जारी हुआ है। गाने को जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल कुणाल वर्मा ने लिखे हैं। पायल देव और आदित्य देव ने मिलकर इसे कंपोज किया है। गाने के दृश्य फिल्म में अभिनेत्री के मेंहदी समारोह पर फिल्माए गए हैं। तेरा यार हूं मैं एक एक रोमांटिक-ड्रामा है, जो 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।

पिछले महीने निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल ट्रैक जारी किया था। अब तुम ही से प्यार जारी हुआ है। गाने को जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसके बोल कुणाल वर्मा ने लिखे हैं। पायल देव और आदित्य देव ने मिलकर इसे कंपोज किया है। गाने के दृश्य फिल्म में अभिनेत्री के मेंहदी समारोह पर फिल्माए गए हैं। तेरा यार हूं मैं एक एक रोमांटिक-ड्रामा है, जो 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।

इसके अलावा फिल्म में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी, नेहा खान, आनंद आचार्य और दर्शन जरीवाला जैसे अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 'तेरा यार हूं मैं' 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

लॉक अप 2 में माधुरी जैन ग्रोवर के बयान पर विवाद, तीसरे बच्चे और अमीरी–गरीबी वाली टिप्पणी से मचा बवाल

रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 अक्सर अपने कंटेस्टेंट्स की निजी बातों और तीखे बयानों को लेकर चर्चा में रहता है। शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि यहां कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी से जुड़े ऐसे खुलासे करते हैं जो कई बार दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और कई बार विवाद भी खड़ा कर देते हैं। इसी कड़ी में इस बार बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर की पत्नी और कंटेस्टेंट माधुरी जैन ग्रोवर का एक बयान सामने आया है, जिस पर लोग अब अलग-अलग राय दे रहे हैं। हाल ही के एक एपिसोड में माधुरी जैन ग्रोवर ने बताया कि वह और उनके पति अशनीर ग्रोवर तीसरा बच्चा चाहते थे लेकिन उनके परिवारों ने इस फैसले का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि परिवार की सहमति न मिलने के कारण उन्होंने यह प्लान छोड़ दिया। हालांकि असली विवाद उनके इस निजी खुलासे से ज्यादा उनके आगे दिए गए विचारों को लेकर शुरू हुआ। शो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया- तीसरा बच्चा इंसान को ज्यादा जवान रखता है। अगर आप देखें तो शाहरुख खान जैसे कई अमीर लोगों के भी तीन बच्चे हैं। हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट हर किसी पर लागू नहीं होता। जितने अमीर लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतनी अमीरी बढ़ेगी और जितने गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतनी गरीबी बढ़ेगी।

उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने इसे गलत सोच और समाज को बांटने वाला बयान बताया।

एक यूजर ने लिखा, यह बयान दिखाता है कि कुछ लोगों को यह समझ नहीं है कि इकॉनोमी कैसे काम करती है या डेमोग्राफी कैसे होती है। इससे बहुत कुछ पता चलता है कि एलीट क्लास के पास जरूरी जानकारी की कमी है। आम जनता ऐसे लोगों को वोट देती है।

दूसरे यूजर ने लिखा, अगर समाज में सिर्फ अमीर लोग ही बच्चे पैदा करें और गरीब लोग न करें, तो उनके पास लेबर नहीं होगी। अमीर अपने बच्चों को आर्म्ड फोर्स में नहीं भेजते, अमीर टेररिज्म/बॉर्डर/सिक्योरिटी से कैसे निपटेंगे? अमीरों को अमीर बने रहने के लिए लेबर की जरूरत होती है।

एक अन्य प्रतिक्रिया में यूजर्स ने इसे एलीट सोच का उदाहरण बताया और कहा, इस तरह के विचार समाज में गलत संदेश देते हैं। हर व्यक्ति को परिवार बढ़ाने का अधिकार है और इसे आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखना ठीक नहीं है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com